04 - 'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

05 - बढ़ती उम्र में अकेलापन और अल्जाइमर : एक गंभीर चुनौती

A Daily News Magazine

भोपाल

शनिवार, 21 सितम्बर , 2024

06 - राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ...

07- देवास के अमृत संचय अभियान को मेपकॉस्ट से...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-24 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

क्या राहुल की चुनौती या मोदी का विकल्प बन सकते हैं केजरीवाल?

रविकान्त

ज मानत पर तिहाड़ से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए कहा था कि वे जनता की अदालत से बरी होकर ही दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे! अब आप की बैठक में आतिशी मार्लेना सिंह को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुन लिया गया। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा? क्या वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय होंगे? केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा के हैं। दस साल की सत्ता विरोधी लहर के कारण भाजपा हरियाणा में फंसी हुई है। कांग्रेस भाजपा को मजबूत टक्कर दे रही है। बावजूद इसके पिछले दिनों कांग्रेस 'आप' के साथ गठबंधन करके कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए दोनों तरफ से पहल हुई। संभवतया राहुल गांधी चाहते थे कि 'आप' के साथ गठबंधन हो। दरअसल, राहुल गांधी सहयोगी दलों को एकजुट रखते हुए 'इंडिया एलायंस' को मजबूत रखना चाहते हैं। लेकिन अंततः बात नहीं बनी। 'आप' ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और 'आप' के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी हमलावर होंगे?

इसीलिए यह भी सवाल उठ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते थे, क्या अब केजरीवाल के सहारे ही राहुल गांधी का प्रतिरोध खड़ा करना चाहते हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि राहुल गांधी की राजनीति के आगे मोदी ब्रांड और अमित शाह की चाणक्य नीति दम तोड़ चुकी है। एक सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल के जरिए राहुल गांधी को रोका जा सकता है?

2012-13 के भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी गठित की और राजनीति में बहुत तेजी से सफलता हासिल की। दिल्ली विधानसभा के लिए अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित जैसी दिग्गज को पराजित किया। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि केजरीवाल ने शीला दीक्षित का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। भाजपा को रोकने के मकसद में कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। पहली बार केजरीवाल कांग्रेस के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बने। जल्द ही कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ और सरकार गिर गई। दूसरे चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने छप्पर फाड़ सफलता प्राप्त की। इस दरम्यान केजरीवाल ने अपने तमाम आंदोलन के सहयोगी एक-एक करके बाहर निकाल दिए अथवा उन्हें खुद से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। केजरीवाल भी सुप्रीमो बन गए। जिन गांधीवादी मूल्यों के आधार पर नई राजनीति की इबारत लिखने का ऐलान करके केजरीवाल राजनीति में आए थे, सब बीते दिनों की बात हो गई।

केजरीवाल ने उन तमाम हथकंडों का सहारा लिया। केजरीवाल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। वे हैडलाइन मैनेजमेंट में माहिर हैं। आगे चलकर केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के उड़नखटोले पर भी सवार हो गए। भाजपा के राम के सामने उन्होंने हनुमान को अपनी हिंदुत्व की राजनीति का प्रतीक बनाया। गांधी के समाधि स्थल पर मौन साधना करने वाले केजरीवाल मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। गुजरात चुनाव में तो केजरीवाल ने मोदी को भी फंसा दिया था; जब उन्होंने भारतीय मुद्रा पर लक्ष्मी और गणेश के चित्र छापने की मांग कर डाली।

केजरीवाल हिंदुत्व का बहुत महीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व से एक मामले में वे जरूर अलग हैं। उनके हिंदुत्व में मुस्लिम विरोध और सांप्रदायिकता नहीं हैं। वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा का जहर नहीं उगलते। तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को उनकी पिच पर अरविंद केजरीवाल ही मात दे सकते हैं। क्या यह सही है कि मोदी का विकल्प केजरीवाल ही हो सकते हैं?

वस्तुतः, व्यक्तित्व और राजनीतिक शैली में मोदी का मुकाबला केजरीवाल ही कर सकते हैं। लेकिन पिछले दो साल में राजनीति काफी बदल चुकी है। हिन्दुत्व के नेरेटिव और छवि की ब्रांडिंग से राजनीति, अब सामाजिक न्याय और सबाल्टर्न शैली पर आ गई है। इस राजनीति के संवाहक राहुल गांधी हैं। उन्होंने हिंदुत्व की वैचारिकी और ब्रांड छवि को ध्वस्त कर दिया। 'भारत जोड़ो यात्रा' से यह सिलसिला शुरू हुआ। अनेक विषम परिस्थितियों में चार महीने तक अनवरत पैदल चलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व को जमकर चुनौती दी। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा के लिए वे डटे रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर-शोर से उठाया। किसानों, कारीगरों, दस्तकारों और मजदूरों से मिलते हुए राहुल गांधी उनके दुख दर्द को साझा करते रहे। नरेंद्र मोदी देश बदलने आए थे और ड्रेस बदलने में लग गए। लेकिन राहुल गांधी ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा मं् केवल सफेद टीशर्ट और पेंट पहना। उन्होंने राजनीति के पारंपरिक स्वरूप को तोड़ दिया। आज राहुल गांधी की पहचान सादगी भरे एक संवेदनशील बौद्धिक नेता की बन चुकी है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने भी ताकतवर राजनीति के मिथ को तोड़ा था। लाल बत्ती और वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की मुनादी करने वाले केजरीवाल ने सत्ता में आते ही अपने ही वादों को तोड़ दिया। बंगला, गाड़ी सबका उपभोग किया। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में आए केजरीवाल खुद शराब नीति घोटाले के आरोप में घिर गए। गांधी के चित्र से राजनीति शुरू करने वाले केजरीवाल ने पंजाब में गांधी को भुला दिया। पंजाब में आप सरकार के चित्रों पर शहीद भगत सिंह और डॉ. आंबेडकर आ गए। वास्तव में, केजरीवाल का आंबेडकर और उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस और बीजेपी की तरह उनके लिए भी आंबेडकर महज प्रतीक हैं। वोट जुगाड़ू राजनीति के प्रतीक! इसी तरह उनका चुनाव चिह्न झाड़ू भी दलितों को जोड़ने का प्रतीक बन गया। राहुल गांधी ने प्रतीकों की राजनीति को भी ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी दलितों के बीच जाते हैं। रामचेत और मिथुन की दुकान पर जाकर उनके हुनर का सम्मान करते हैं। उनके अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। राहुल गांधी आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना कराने की मांग करते हैं। जबकि केजरीवाल आरक्षण विरोधी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। केजरीवाल पॉपुलर पॉलिटिक्स के रोल मॉडल हैं। जबकि राहुल गांधी सबाल्टर्न पॉलिटिक्स के पैरोकार हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ना तो राहुल गांधी की चुनौती बन सकते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी का विकल्प।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

अब भारत की आर्मी भी होगी हाईब्रिड वारफेयर की खिलाड़ी

सीडीएस अनिल चौहान ने बताया प्लान,कहा-अब युद्ध की प्रकृति बदल गई है

सीडीएस ने कहा-हमने भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम जैसी चीज पर चर्चा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया के बड़े-बड़े संघर्ष जंग के मैदान में ही हुए हैं, लेकिन अब इनके लिए किसी मैदान-ए-जंग की जरूरत नहीं रह गई है। इसकी वजह यह है कि युद्ध की प्रकृति ही बदल गई है। इसी सप्ताह हमने देखा है कि कैसे इजरायल ने दुश्मन हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी-टॉकी में ही विस्फोट करा दिए। इससे करीब 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3000 लोग जख्मी हुए हैं। इसे भविष्य के युद्धों का एक उदाहरण माना जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन वारफेयर, साइबर वारफेयर आदि भी चिंता का

विषय हैं। इन सभी के मिले-जुले स्वरूप को जानकार हाइब्रिड वारफेयर का नाम देते हैं। इस बीच भारतीय सेना भी हाइब्रिड वारफेयर को लेकर ऐक्टिव हो गई है। इसके लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करने पर भी जोर है। इसके तहत पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसकी जानकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध पर आधारित पहला पाठ्यक्रम 23 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें विभिन्न रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने भारत शक्ति रक्षा सम्मेलन में एक संवाद सत्र में रूपरेखा के बारे में भी बात की।

कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है

पीएम मोदी ने कहा-इन्हें भगवान गणपति से भी है चिढ़

कहा-मैंने गणेश पूजा की तो पूरी पार्टी ही बेचैन हो गई

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। वे विदेश से बैठकर एजेंडे चलाते हैं। इन्हें अब गणपति बप्पा से भी चिढ़ होने लगी है। मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। मोदी ने यह बातें महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली को संबोधित की। वे यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के एक साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। पीएम ने कहा- पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस और उनके दोस्तों ने एससी/एसटी को दबाकर रखा। उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय बनाया। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। एक साल में इस योजना के तहत 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया, तो कांग्रेस का तुष्टिकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। दरअसल पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन करने गए थे।

सुप्रभात

अंजुरी भर जल छोड़ा रोज़...
और मन भर लिया कि
तुम अपने घर से प्यासे नहीं लौटे हो
पर जिस घर की भूख के इंतज़ाम में
तुम भूले रहे अपनी हर प्यास....
वो तो अधूरी है अब तक
प्यास पानी की ही तो नहीं होती हमेशा....
तुम्हारे जाने के बाद ये समझ आया हमें
कि मन भर जी लेने की प्यास
किसी अंजुरी में नहीं समाती....
तुम्हारे नाम का निवाला निकाला रोज़
थाली में समेटा तुम्हारा इच्छा भोज
इसमें कहां शामिल है
जवानी में सफेदी ओढ़ चुकीं
हसरतें तुम्हारीं.....
ज़रुरतों से हारकर हर बार छोड़ी जाती रहीं
मुट्ठी भर कामनाएं तुम्हारी...
तुम्हारी इच्छाओं के होम के बदले...
अब कितने जतन....
कि तुम्हे तृप्ति मिल जाए.....
तुम्हारे जाने के बाद ये समझ आया हमें
कि तुम्हारी तृप्ति के सारे मार्ग
इस थाली ने तो छीने थे.....।

- शिफाली

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलकाता में इन्वेस्टर्स समिट का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया

काम कराना है, तो मन बड़ा करें : सीएम यादव

कहा- बिजनेसमैन के लिए सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है, इसे सीधा करना है

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है। इसे बदलना है। हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना होगा। पॉलिसी से भी आगे जाना है, तो सरकार तैयार है। एमपी में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पांवड़े बिछाने को तैयार है। काम कराना है, तो मन बड़ा करना पड़ेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश आइए।

मुख्यमंत्री ने यह बात कोलकाता में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कही। वे शुक्रवार को इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। यादव ने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल और कोलकाता में तालमेल है।

हम जियो और जीने दो पर विश्वास करते हैं- सीएम डॉ. यादव ने कहा कि जीआईएस (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) मध्यप्रदेश में पहले एक ही शहर में होती थी। हमने इसे बदला। एमपी से कॉटन देशभर में जाता है। रेडीमेड गारमेंट की संभावना है। आपने कोयंबटूर में इंडस्ट्री लगाई है, तो एमपी में भी आमंत्रण देते हैं। माइनिंग सेक्टर, एनर्जी और टूरिज्म सेक्टर समेत सभी सेक्टर में सरकार सहयोग करने को तैयार है।

सीएम ने कहा कि कोलकाता प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र है। मध्य प्रदेश भी खनिज संसाधनों और कृषि

उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोनों राज्यों के बीच कई उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों और कृषि उत्पादों का लेन-देन होता है। मध्यप्रदेश के उत्पाद जैसे सोयाबीन, गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद की पश्चिम बंगाल में मांग है, जबकि पश्चिम बंगाल के जूट, चाय और मछली उत्पाद मध्य प्रदेश में भी लोकप्रिय हैं।

कोलकाता से भोपाल, जबलपुर के लिए फ्लाइट मांगी- समिट में एमपी बिरला ग्रुप के एमडी संदीप घोष ने कहा कि 70 साल पहले सतना में पहला सीमेंट प्लांट लगा था। सतना सीमेंट के नाम से बिरला सीमेंट जाना जाता था। इस दौरान एमपी का जो ट्रांसफार्मेशन हुआ है, वह देखने लायक है। चेंज विद कंटीन्यूटी के साथ हुए बदलाव का असर देखने को मिलता है। रीवा में व्हाइट टाइगर और यूनिवर्सल केबिल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। मैहर में भी सीमेंट प्लांट लगाया है। कोलकाता से भोपाल, जबलपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इसे शुरू करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरू में एचएएल में विजिट कर कामकाज को देखा था।

पीएस राघवेंद्र सिंह ने बताई उद्योग पॉलिसी

प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने इंटरेक्टिव सेशन में प्रदेश सरकार की उद्योग पॉलिसी के बारे में बताया। एमपी में कॉपर, मैंगनीज समेत अन्य बहुमूल्य खनिज उपलब्ध हैं। उन्होंने अलग-अलग इंडस्ट्रियल एरिया और उसमें संचालित उद्योगों की जानकारी भी कोलकाता के निवेशकों को दी। उन्होंने रोजगार सृजन की स्थिति में सब्सिडी दिए जाने के बारे में भी बताया। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, आईटी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं के बारे में भी बताया।

एसीएस संजय दुबे ने कहा- एमपी में नो रिस्क बिजनेस

मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे ने एमपी में आईटी और ईएसडीएम सेक्टर में किए जाने वाले निवेश की विशेषताओं की जानकारी दी। उन्होंने एमपी में मौजूद स्किल पॉवर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 आईटी पार्क में 50 हजार सुपर क्वालिफाइड स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं। दुबे ने कहा कि एमपी में नो रिस्क बिजनेस की स्थिति है। सात साल से देश के स्वच्छतम शहर इंदौर और क्लीनेस्ट कैपिटल भोपाल की विशेषताओं की जानकारी देते हुए एसीएस दुबे ने कहा कि 1200 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं।

तिरुपति के लड्डुओं पर बढ़ता जा रहा है विवाद

जेपी नड्डा ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए बनाए जाने वाले लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिली। इसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। टीडीपी ने इसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, तो वहीं बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू से जानकारी मांगी है।

दरअसल, तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, इस बारे में जानकारी मिलने के बाद मैंने आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से बात की और उनसे विस्तृत जानकारी ली। मैंने उनसे उपलब्ध रिपोर्ट साझा करने को कहा है ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं। मैं राज्य नियामकों से भी बात करूंगा और इसकी जांच करूंगा। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैंने रिपोर्ट मांगी है और हम इसकी जांच करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस घी की कीमत 20,000 करोड़ रुपये है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछली सरकार ने श्रीजा से घी नहीं खरीदा, जो दुनिया की सबसे बड़ी महिला स्वामित्व वाली संस्था है। सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए कि घी किस कीमत पर खरीदा गया और चर्बी युक्त घी क्यों खरीदा गया। इसके अलावा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदू समुदाय के साथ घोर अन्याय है।

'हथियार छोड़ दें नक्सली', नहीं तो शुरू होगा बड़ा वार

अमित शाह बोले-नहीं माने तो अब शुरू करेंगे ऑपरेशन ऑल आउट

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने, हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी, अगर नक्सली हिंसा छोड़ने की मेरी अपील नहीं मानते हैं तो हम जल्द ही उनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे। मैं

अपील करता हूं कि वे कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, अपने हथियार छोड़ दें। पूर्वोत्तर और कश्मीर में कई जगहों पर कई लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके खिलाफ अभियान शुरू करेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 36.3 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शनिवार, 21 सितम्बर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

थाने में आर्मी ऑफीसर से मारपीट, मंगेतर का यौन उत्पीड़न

● पीड़ित बोली-मेरे हाथ-पैर बांधे, कपड़े उतारे,

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला आर्मी ऑफीसर के साथ रोड

रेज की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी। थाने में पुलिसकर्मियों ने उनसे पहले बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की और हाथ-पैर बांध दिए। पीड़ित के मुताबिक, एक पुरुष अधिकारी ने उनके अंडरगार्मेंट उतारे। फिर छाती पर लातें मारीं।

46 लोगों की एक जन्मतिथि, शिमला में किराए पर दुकानें

● मस्जिद के बाद मुस्लिमों के 'आधार' पर बवाल

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ। इस बीच शिमला में बाहर से आए व्यापारियों के आधार कार्ड को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस लेकर शिमला जिले के कोटखाई व्यापार

मंडल और गुम्मा व्यापार मंडल ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उनके क्षेत्र में काम कर रहे बाहरी मुस्लिम व्यापारियों के आधार कार्ड पर एक ही जन्मतिथि (1 जनवरी) अंकित है।

24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे

● एआईएमआईएम का पलटवार-हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने शुक्रवार को संगोली में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं सिर्फ 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी दे दी जाए। इसके बाद हम (हिंदू) अपनी ताकत

दिखा देंगे। हम उन्हें यह एहसास दिला देंगे कि हममें कितना दम है। नितेश राणे के इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आए दिन यह लोग अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव से पहले बीजेपी यहां का माहौल खराब करना चाहती है।

अहमद, तुम कैसे हो... तुम्हारी रीना!

एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप

● एमपी के छतरपुर में नाराजगी, तमतमाए हुए तुरंत थाने पहुंचे बच्ची के पिता ● हिंदू लड़की रीना के मुस्लिम लड़के अहमद को पत्र लिखने पर गरमाया विवाद

छतरपुर (एजेंसी)। एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक अभिभावक ने छतरपुर पुलिस में लिखित शिकायत दी है। यह आपत्ति डॉक्टर राघव पाठक नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। राघव पाठक का आरोप है कि एनसीईआरटी की तीसरी क्लास में पर्यावरण विषय के 17 नंबर पेज से उन्हें आपत्ति है। इस पेज में 'चिट्ठी आई है' नाम का एक शीर्षक है, जिसमें रीमा नाम की लड़की अहमद को छुट्टियों में अगरतला आने का निमंत्रण देती है और अंत में लिखती है तुम्हारी रीना। राघव पाठक ने खजुराहो एसडीओपी को लिखित में एक शिकायती आवेदन देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। डॉक्टर राघव पाठक का कहना है कि मेरी बेटी कक्षा तीसरी में पढ़ती है। एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक की पेज

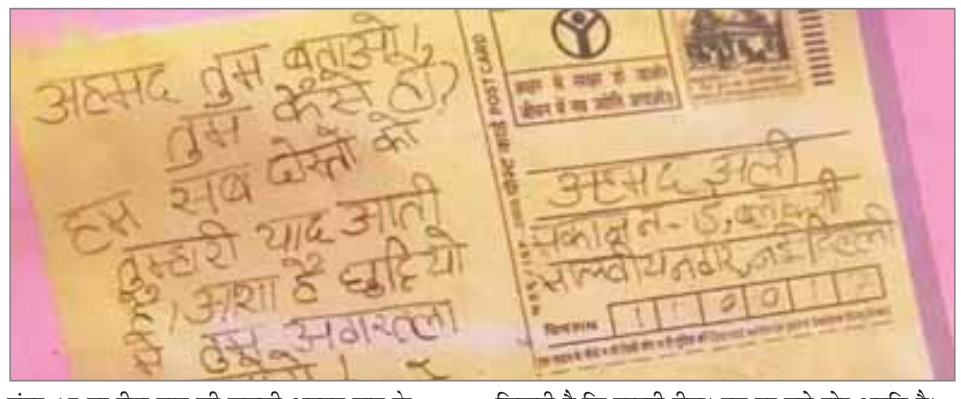

नंबर 17 पर रीना नाम की लड़की अहमद नाम के लड़के को एक पत्र लिखती है और पत्र के अंत में वह लिखती है कि तुम्हारी रीना। इस पर मुझे घोर अपत्ति है। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के को पत्र लिख रही है और अंत में वह अपने आप को उसका बताती है। इससे साफ जाहिर है कि छोटे बच्चों के मन में लव जिहाद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आने वाले समय में लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। एक ओर सरकार लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है दूसरी ओर एनसीईआरटी की यह किताब लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। राघव ने कहा मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के 17 नंबर पेज पर जिस चिट्ठी में अहमद और रीमा का जिक्र है, उसे बदला जाए या फिर इसे हटा दिया जाए। मैं भी एक पिता हूं और मेरी बेटी इस किताब को पढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में किसी भी तरह के कोई गलत भाव पैदा हों। मामले में खजुराहो एसडीओपी का कहना है कि डॉ राघव पाठक ने लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

पेजर, वॉकी-टॉकी के बाद अब की धमाकेदार एयरस्ट्राइक

● इजराइल ने लेबनान पर किए 70 से ज्यादा हमले, दहशत का माहौल
● हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट बैरल तबाह, हथियार डिपो भी बर्बाद हुआ

बेरूत (एजेंसी)। लेबनान में पिछले तीन दिन से पेजर, वॉकी-टॉकी और फिर सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाकों के बाद इजराइल ने गुरुवार रात दक्षिणी लेबनान में 70 हवाई हमले किए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया है। इनमें 1000 रॉकेट बैरल तबाह हो गए। आईडीएफ ने कहा कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजराइली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया। इससे पहले लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी-टॉकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2300 लोग घायल हुए थे। लेबनान और हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया

है। आईडीएफ की सलाह- बम शेल्टरों के करीब रहें इजराइली नागरिक हमले के बाद आईडीएफ ने नॉर्थ इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें उनसे बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजराइली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है।

भारत ने तरेरी आंखें तो गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान

● सिंधु जल संधि का सम्मान करने का किया आग्रह

इस्लामाबाद (एजेंसी)। सिंधु जल संधि की समीक्षा लेकर भारत द्वारा भेजे गए औपचारिक नोटिस का जवाब पाकिस्तान से आ गया है। इस्लामाबाद की तरफ से कहा गया है कि वह इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। दरअसल, पाकिस्तान का यह जवाब भारत के उस नोटिस के बाद आया है जो 30 अगस्त को भेजा गया था। भारत की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में 64 साल पुराने समझौते की समीक्षा की मांग की गई थी। इसका कारण भारत ने तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में बदलाव और पाकिस्तान द्वारा लगातार फैलाए जा रहे सीमा पार के आतंकवाद का

हवाला दिया था। भारत के नोटिस का जवाब देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल संधि को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल धाराओं का एक तंत्र है और संधि से जुड़े सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि संधि से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई भी कदम समझौते के प्रावधानों के तहत ही उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान उस समझौते में संशोधन में रुचि नहीं रखता है।

लैंड फॉर जॉब स्कैम में बढ़ी लालू यादव की मुश्किल

पूर्व सीएम के खिलाफ चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी

पटना (एजेंसी)। लैंड फॉर जॉब स्कैम में गृह मंत्रालय ने सीजेआई को लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राऊज एवेन्यू कोर्ट में दी है। सीबीआई ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को 'नौकरी के बदले जमीन' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। उन्हें 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई प्रमुख लोगों को समन जारी किया है। यह पहला मौका है

जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, शुरुआत में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन वे एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है। विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। अन्य आरोप-पत्रित व्यक्तियों को भी समन भेजा गया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी अपने समन में शामिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया था।

2015-कैश फॉर वोट केस तेलंगाना से भोपाल नहीं होगा ट्रांसफर

● सुप्रीम कोर्ट का सीएम रेड्डी को निर्देश-एंटी करप्शन ब्यूरो के काम में दखल न दें

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से जुड़े 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले को तेलंगाना से भोपाल ट्रांसफर करने से मना कर दिया। याचिका बीआरएस विधायक गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी ने लगाई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने रेड्डी को निर्देश दिया कि वे मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो के कामकाज में किसी भी तरह से दखल न दें। कोर्ट ने कहा, एसीबी डायरेक्टर मामले के बारे में तेलंगाना के सीएम को रिपोर्ट नहीं करेंगे।

हम उम्मीद करते हैं संविधान के तीन अंग (विधायिका-कार्यपालिका-न्यायपालिका) एक-दूसरे के काम को सम्मान देंगे। मई 2015 में एसीबी ने ही रेड्डी को विधान परिषद चुनावों में टीडीपी उम्मीदवार को सपोर्ट के बदले 50 लाख की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया था।

आज की राजनीति में जहर घुल चुका है...

● प्रियंका गांधी बोलीं-पीएम मोदी ने क्यों नहीं दिया पत्र का जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से लिखे गए पत्र पर प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की राजनीति में जहर घुल चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष ने हीनतर और आक्रामक किस्म का जवाब भेजा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की अनर्गल और हिंसक बयानबाजी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए की गई।

युद्धपोत, पनडुब्बी और 40000 सैनिक...जबरदस्त बनाया घेरा

● इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका की तीनों सेनाएं मौजूद, हर पल युद्ध के लिए तैयार

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका ने लगभग एक साल से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई हुई है। लगभग 40 हजार सैनिक, कम से कम एक दर्जन युद्धपोत, चार वायुसेना लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। ऐसा इसलिए ताकि अमेरिका अपने सहयोगियों के खिलाफ होने वाले हमलों को रोक सके। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव ने फिर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस कारण संघर्ष एक

पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। इजरायल का हमास के खिलाफ हमला भी लगभग एक साल से चल रहा है। हिजबुल्लाह ने पेजर हमले के बाद कहा है कि इजरायल ने सारी हदें पार कर दी हैं। पहले से ही मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना है। नवीनतम हमलों ने सेना में वृद्धि या बदलाव का संकेत नहीं दिया है। आम तौर पर 34000 अमेरिकी सेनाएं कमांड में तैनात की जाती हैं।

आज से बंगाल के सरकारी अस्पतालों में बहाल होंगी सेवाएं

● मान गए प्रदर्शनकारी डॉक्टर, इमरजेंसी ड्यूटी पर लौटने का ऐलान ● आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर मामले के बाद प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। डॉक्टर्स कल शनिवार से काम पर वापस लौटेंगे। हालांकि, अभी इमरजेंसी सेवाएं ही खुलेंगी, जबकि ओपीडी सेवाएं चालू नहीं होंगी। जूनियर डॉक्टर्स 9 अगस्त की रेप की घटना के बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने समेत पांच मांगें रखी थीं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगों को मान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने के लिए कहा था। आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कहा, शनिवार से बंगाल के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन, आवश्यक सेवाएं आंशिक रूप से बहाल होंगी।

बंगाल में बाढ़ प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा,न्याय के लिए हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक डॉ. अकीब ने कहा कि वे विरोध को अलग तरीके से लेंगे। विरोध के 41वें दिन, उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट यह कहना चाहता है कि हमने अपने आंदोलन के दौरान बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कई चीजें अभी भी हासिल नहीं हुई हैं... हमने कोलकाता के पुलिस आयुक्त और डीएमई, डीएचएस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है। हम इसे नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अकीब ने कहा, हम अभी भी मांग करते हैं कि प्रमुख सचिव को हटाया जाए। गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा और कुशल कामकाज पर निर्देशों की एक सूची जारी करते हुए कहा है कि इन्हें तुरंत लागू करने की जरूरत है। ये निर्देश सरकार द्वारा इन्हीं मुद्दों पर आंदोलनरत कनिष्ठ चिकित्सकों के साथ बैठक के एक दिन बाद जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव मनोज पंत द्वारा प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) एन एस निगम को भेजे गए दो पृष्ठों के पत्र में, स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी कक्ष,शौचालय सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता की आवश्यकता का उल्लेख है।

रूस और पाकिस्तान में दोस्ती, भारत के लिए टेंशन

● पुतिन का महाकॉरिडोर प्लान, हिंद महासागर तक होगी सीधी पहुंच

मास्को (एजेंसी)। पाकिस्तान और रूस तथा बेलारूस के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। पाकिस्तान अब सीधे रूस और बेलारूस से सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है। यह मल्टी मॉडल कॉरीडोर बेलारूस, रूस, कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचेगा। इससे रूस आगे चलकर पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर के बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। पाकिस्तान इस मल्टीमॉडल कॉरिडोर से जुड़ गया है। उज्बेकिस्तान के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। उसने बताया कि इस समझौते के बाद व्यापार, आर्थिक रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तथा सामान का इस इलाके में आना जाना आसान हो जाएगा।

बच्ची से रेप के पहले आरोपी टीचर ने देखी पोर्न क्लिप

भोपाल में आरोपी के मोबाइल में 100 से ज्यादा क्लिप डाउनलोडिंग के मिले प्रूफ

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी टीचर कासिम रेहान के मोबाइल की डेटा हिस्ट्री में 100 से ज्यादा पोर्न फिल्म की क्लिपिंग डाउनलोड किए जाने के प्रूफ मिले हैं, जो मासूम बच्चियों के साथ यौन हिंसा से जुड़ी हुई हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। उसने बताया कि स्कूल में फ्री समय में वारदात से पहले पोर्न क्लिप देखी थी। इसके कुछ ही देर बाद उसे वॉशरूम में जाती बच्ची दिखी। वॉशरूम में उसने बच्ची से अश्लील हरकत की।

बता दें, बुधवार को कमला नगर थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

4-5 दिन से मासूम की निगरानी कर रहा था- आरोपी टीचर कासिम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह 4-5 दिन से मासूम बच्ची के स्कूल आने, क्लास से बाहर जाने और वॉशरूम तक जाने की निगरानी कर रहा था।

घटना वाले दिन बच्ची जब वॉशरूम गई, तो वह भी उसके पीछे-पीछे चला गया। वॉशरूम में उसके साथ गलत काम किया। यह पूरा घटनाक्रम दो से ढाई मिनट के अंदर हुआ। इसके बाद बच्ची अपने क्लास रूम में चली गई।

बच्ची को किसी को नहीं बताने की दी हिदायत- आरोपी ने वारदात के बाद बच्ची की एक्टिविटी की निगरानी की थी। घटना के करीब आधे घंटे बाद बच्ची दोबारा क्लास रूम से बाहर निकली, तब बच्ची को वॉशरूम में हुई घटना किसी को भी नहीं बताने के बारे में हिदायत दी थी। साथ ही टॉफी का लालच दिया था।

आरोपी बोला- बच्ची आसान टारगेट लग रही थी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 साल की छोटी बच्ची उसे आसान टारगेट लग रही थी। अनुमान था कि बच्ची किसी को भी इस संबंध में नहीं बताएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी कॉन्स्टेबल मां के पूछने पर वॉशरूम में बेड टच के बारे में बता दिया।

बच्ची से ज्यादती के अगले दिन भी स्कूल गया आरोपी

वारदात के अगले दिन भी आरोपी स्कूल पहुंचा, उसे लगा कि सब ठीक है, उसका कुछ नहीं होगा। इसके अगले दिन बच्ची के परिजन ने शिकायत थाने में कर दी। तब उसे स्कूल स्टाफ ने स्कूल तलब किया। यहां आते ही पुलिस ने स्कूल से ही उसकी गिरफ्तारी कर ली।

जांच टीम ने दर्ज किए प्रिंसिपल और शिक्षकों के बयान

टीटी नगर एसडीएम डॉ. अर्चना शर्मा की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने गुरुवार को प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल और महिला शिक्षकों के बयान दर्ज किए। सूत्रों के मुताबिक प्रिंसिपल ने बताया कि पीड़ित बच्ची के पेरेंट्स घटना की शिकायत लेकर उनसे नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी कासिम रेहान स्कूल में बतौर टीचर कार्यरत नहीं था। वह आईटी प्रोफेशनल के पद पर था।

एसआईटी ने दर्ज किए बच्ची के स्टेटमेंट, वीडियोग्राफी भी कराई

एसीपी महिला सुरक्षा और एसआईटी चीफ निधि सक्सेना ने बताया- गुरुवार दोपहर बच्ची और उसके मां-पिता थाने आए थे। यहां बच्ची की काउंसिलिंग के लिए बाल कल्याण समिति से एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त कराया है। इसके बाद बच्ची के स्टेटमेंट लिए गए। स्टेटमेंट की वीडियोग्राफी भी हुई है। साथ ही, बच्ची के मां-पिता के स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए सात दिन में ही चालान पेश करने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी के मोबाइल में दो महिला मित्रों से चैटिंग मिली

आरोपी के मोबाइल में उसकी दो महिला मित्रों से चैटिंग भी मिली है। इनमें से एक महिला मित्र से आरोपी की पिछले 18 महीने से बातचीत बंद है। संबंधित महिला मित्र से आरोपी की बातचीत क्यों बंद हुई? इस बारे में पूछताछ में कासिम ने पुलिस को स्वयं को शक्की मिजाज का होना बताया है। जबकि दूसरी महिला मित्र से उसकी बातचीत जारी है, लेकिन संबंधित को आरोपी कासिम ने रिश्तेदार बताया है। इसके चलते पुलिस आरोपी के इन बयानों की भी जांच कर रही है।

भोपाल में लघु वेतन कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

स्थाईकर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करने की मांग

भोपाल (नप्र)। जनजाति कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के हाईस्कूल, हायर सेकंडरी स्कूल एवं सभी छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं किए जाने से नाराज मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को भोपाल में आयुक्त जनजाति कार्य विभाग का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा

ने बताया कि कुछ जिलों में मजदूरी मद आवंटन नहीं किए जाने के कारण 9-10 माह से इन कर्मचारियों का समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।

शर्मा ने बताया कि संघ ने इस मुद्दे को कई बार उठाया। संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, पर निराकरण करने पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण प्रदेशभर में कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि भोपाल में सतपुड़ा भवन के सामने प्रदर्शन किया गया, जबकि जिलों में संबंधित कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भोपाल में ज्ञापन सौंपने गए कर्मचारियों को आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने भरोसा दिलाया कि मांगों का निराकरण जल्द कराएंगे।

शर्मा ने बताया कि ज्ञापन के पूर्व सतपुड़ा भवन परिसर में प्रदर्शन एवं नारेबाजी की गई, जिसमें भोपाल के सभी विभागीय समितियों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिसमें मुख्य रूप से संघ के निर्णय समिति के मार्गदर्शक निहाल सिंह जाट, अध्यक्ष मांगीलाल तमोली, महामंत्री धर्मेंद्र शर्मा, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष सुधीर भार्गव, शिक्षा समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पंकज संगत, जिला शाखा अध्यक्ष राम कुंडल सेन, उपप्रांत अध्यक्ष कैलाश लाल सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

भोपाल में 5वीं मंजिल से गिरी 9वीं की छात्रा, मौत

घटना से पहले 6 घंटे तक लापता थी; पुलिस बोली- पैर फिसलने से हुआ हादसा

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 9वीं कक्षा की छात्रा पांचवी मंजिल में स्थित फ्लैट की बालकनी से गिर गई। छात्रा हादसे से पहले 6 घंटे तक लापता थी। मामले में पुलिस का कहना है कि कपड़े सुखाते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ है। वहीं, बिल्डिंग के रहवासी और माली ने बताया कि किशोरी ने खुदकुशी की है। घटना कोलार में स्थित अल्टीमेट कैंपस की है।

एसआई जितेंद्र केवट के मुताबिक रिया कटारे (15) के पिता राजेश कुटारे पुलिस डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं। गुरुवार की शाम को बंसल अस्पताल से सूचना मिली की किशोरी फ्लैट की पांचवीं मंजिल से गिरी है। परिजनों ने कपड़ा सुखाते समय पैर फिसलने की बात कही है। पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी है।

इसलिए संदिग्ध लग रहा मामला- कॉलोनी में

राजेंद्र माली पेड़ पौधों की देर-रेख का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हादसा करीब 4:15 बजे का है। इस समय वह घटना स्थल से करीब 50 मीटर की दूरी पर काम कर रहा था। तभी कलियासोत नहर में मछली पकड़ रहे युवकों ने शोर किया। आवाज देकर बताया कि लड़की ने छलांग लगा दी है। आनन-फानन में परिजन नीचे आए, उसे लेकर अस्पताल गए। जिस फ्लैट में लड़की रहती थी। वहां दो बालकनी हैं। एक रोड की ओर, दूसरी पिछले हिस्से में कलियासोत नहर की तरफ। छात्रा ने कलियासोत नहर की तरफ वाली बालकनी से लड़की ने छलांग लगाई थी।

बालकनी का जाल हटाकर लगाई छलांग

फ्लैट की सुरक्षा के लिए बालकनी को जाल लगाकर कवर किया है। लड़की ने इस जाल को सरकाने के बाद छलांग लगाई है। यहीं काम करने वाले एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह 10 बजे लड़की बिन बताए घर से निकली थी। उसके पिता और भाई उसे तलाशते रहे थे। शाम को चार बजे किशोरी लौट आई थी। इस बीच परिजन पुलिस को उसकी गुमशुदगी की सूचना दे चुके थे। घर लौटने के चंद मिनट बाद ही उसने सुसाइड कर लिया। लड़की के पिता कॉलोनी में पुलिस के वाहन से आते थे। वह स्वयं को इंस्पेक्टर बताते हैं।

फ्लैट में लगा ताला

हादसे के बाद परिजन बॉडी लेकर रवाना हो गए हैं। फ्लैट में ताला लगा है। बताया जा रहा है कि फ्लैट में बीते 8 महीने से रहे थे। रिया परिवार में सबसे छोटी थी। उसके दो बड़े भाई तथा दो बड़ी बहन हैं। एक बहन ग्वालियर में पढ़ रही है। दूसरी की शादी हो चुकी है।

चौक जिनालय भोपाल में साधिका पूजाश्री को दी विनयांजलि

आर्यिकाश्री ने कहा- मनुष्य को धर्म का बीजारोपण सही समय पर करना चाहिए

भोपाल (नप्र)। राजधानी के चौक जिनालय में शुक्रवार को विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज जैन व मंत्री मनोज आर एम ने बताया कि आर्यिका संघ के सानिध्य में साधिका पूजाश्री को विनयांजलि देने के लिए सभा का आयोजन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल द्वारा किया गया।

इस मौके पर आर्यिकाश्री दृढ़ मति माताजी ने कहा कि कुछ जीव पुण्यशाली होते हे जो अपने अंतिम समय धर्म की शरण में आते हैं,

कुछ समय पूर्व हमारे पास एक श्रविका अपने ससुराल एवं मायके पक्ष के साथ आई और उन्होंने बताया की असाध्य रोग होने के कारण डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और अब गृहस्थ जीवन का त्याग चाहती हूं। उन्हें दस प्रतिमा का व्रत दिया गया और उनकी सल्लेखना की गई। इस मौके पर अध्यक्ष मनोज जैन,मंत्री मनोज आर एम, पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, पंकज जैन, समाज सेवी जिनेन्द्र जैन, राकेश ओसडी, अनिल कोलार, सुधीर जैन, राजेश जैन ने दो मिनट का मौन रखकर विनयांजलि दी।

भोपाल मेट्रो के अंडरग्राउंड रूट पर मिट्टी की टेस्टिंग

प्लेटफार्म नंबर-6 पर बनेगा स्टेशन; यहीं से जमीन के अंदर से गुजरेगी मेट्रो

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मेट्रो के 3.39 किमी अंडरग्राउंड रूट पर मिट्टी की टेस्टिंग शुरू हो गई है। अगले 1 महीने के अंदर मिट्टी की टेस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। इस टेस्टिंग में पता लगाएंगे कि कितनी पथरीली जमीन या पानी है। इस हिसाब से अंडरग्राउंड रूट पर काम शुरू होगा। इधर, आरा मशीनों और अतिक्रमण को हटाने

की फाइनल तैयारी हो गई है। एसडीएम आशुतोष शर्मा ने इसे लेकर मीटिंग भी की है।

मेट्रो से जुड़े अफसरों के अनुसार- रेलवे स्टेशन के पास खाली मैदान पर ही टर्नल बोरिंग मशीन से अंडरग्राउंड रूट की खुदाई होगी। यह मशीन मिट्टी की टेस्टिंग के बाद पहुंचेगी। यही मशीन 3.39 किमी अंडरग्राउंड रूट की खुदाई करेगी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-6 के पास मेट्रो स्टेशन बनेगा।

दूसरे फेज में बनेंगे 8 मेट्रो स्टेशन

भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे फेज सुभाष नगर से करोंद तक 8.77 किमी लाइन बिछाने में कुल 1540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें 8 मेट्रो स्टेशन भी है, जबकि 3.39 किमी रूट अंडरग्राउंड होगा और इसी में 2 मेट्रो स्टेशन भी रहेंगे।

लोकसभा चुनाव से पहले दूसरे फेज के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली भूमिपूजन किया था। इसके बाद काम की शुरुआत हो गई। पुराने शहर में मिट्टी का परीक्षण हो चुका है। अब अंडरग्राउंड रूट पर भी काम हो रहा है।

रिटायर्ड आर्मीमेन ने फांसी लगाकर खुदकुशी की

पिता बोले शराब अधिक पीता था बेटा, डिप्रेशन में था

भोपाल (नप्र)। नीलबढ़ इलाके में रिटायर्ड आर्मीमेन ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नहीं मिला है। आज एफएसएल की अगुवाही में मृतक के कमरे की तलाशी ली जाएगी।

फिलहाल कमरे को सील कर दिया गया है। शुक्रवार को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। शव का अंतिम संस्कार रायसेन में स्थित मृतक के पुश्तैनी गांव में किया जाएगा।

रातीबड़ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 45 वर्षीय प्रमोद पांडे विशाल नगर नीलबड़ में रहते थे। वे सेना नायक हवलदार के पद से सेवानिवृत्ति ले चुके थे। गुरुवार की दोपहर खाना खाने के बाद उन्होंने दवाई खाई तथा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। शाम पांच बजे तक जब वे कमरे से बाहर नहीं आए तो पत्नी अल्पना पांडे उन्हें जगाने के लिए गईं।

यहां पर उन्होंने पति प्रमोद को फांसी के फन्दे पर लटका पाया। वे उन्हें अस्तपाल लेकर पहुंची जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्ट्म के लिए रवाना किया।

पिता बोले अधिक शराब पीने लगा था बेटा

मृतक के पिता एमपी पांडे ने बताया कि बेटा शराब अधिक पीने लगा था। सेना से रिटायर्ड होने के बाद वह प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में बतौर गार्ड नौकरी कर रहा था। बीते तीन सालों से शराब अधिक पीने लगा था। पत्नी द्वारा शराब पीने से रोकने पर उसका विवाद होता था। बीते कई दिनों से डिप्रेशन में था। कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पीने में उड़ा दिया करता था।

यही कारण है कि आर्थिक तंगी से भी जूझने लगा था। खुदकुशी के चार दिन पहले उसने मुझे से दो हजार रुपए ऑन लाइन मांगे थे। मैने परेशानी के संबंध में पूछा तो कुछ भी नहीं बताया। सुसाइड के सही कारणों की जांच पुलिस कर रही है।

भोपाल में बिल्डर दंपत्ति ने की 30.60 लाख की जालसाजी

बैंक में बंधक रखे प्लॉट को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया, एफआईआर दर्ज

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहपुरा इलाके में एक बिल्डर दंपत्ति ने 30.60 लाख रुपए की जालसाजी की। आरोपियों ने बैंक में बंधक रखे प्लॉट को बेच दिया। जबकि फरियादी डॉक्टर ने उक्त प्लॉट को बैंक से ऑक्शन के माध्यम से खरीदा था। फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर पीड़ित डॉक्टर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिल्डर दंपत्ति और बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के मुताबिक मुंबई में रहने वाले चंद्रशेखर सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ऑक्शन में खनुजा ऐनक्लेव शाहपुरा में एक प्लॉट खरीदा था। जिसकी रजिस्ट्री भी बैंक में करा दी थी, लेकिन जब वह प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि बिल्डर रविंद्र खनूजा, उनकी परमजीत खनूजा ने बैंक में बंधक रखे प्लॉट को पहले ही बेच दिया है।

जालसाजी कर रजिस्ट्री भी करा दी

इतना ही नहीं उसकी रजिस्ट्री भी करा दी है। इस बात का पता चलने पर डॉक्टर ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिल्डर दंपत्ति और बैंक मैनेजर कैलाश अहिरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच के बाद पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मीटिंग से गायब स्मार्ट सिटी सीईओ, भड़के सांसद-विधायक

भोपाल के प्रभारी मंत्री बोले- ऐसे अफसर को हटाया जाए; स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर नाराजगी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप की पहली मीटिंग में स्मार्ट सिटी के सीईओ किरोड़ीलाल मीना गायब रहे। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मीटिंग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर काफी असंतोष था। सीईओ भी मौजूद नहीं थे। यह ठीक नहीं है। सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से निर्देश दिए हैं कि इस तरह के अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। कलेक्टर से कहा है कि सीईओ के बारे में उचित निर्णय लें। इधर, सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा भी सीईओ के गायब होने पर भड़क उठे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री काश्यप की अध्यक्षता में दोपहर 12.30 बजे से कलेक्टोरेट में जिले की समीक्षा बैठक शुरू हुई, जो करीब 2 घंटे चली। सांसद आलोक शर्मा, महापौर मालती राय,जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवार गुर्जर,विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, विष्णु खत्री ,कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी आदि भी मौजूद हैं। मीटिंग में शहरी और गांवों की जर्जर सड़कों को लेकर चर्चा की गई। गोवंश के लिए गोशाला और गांवों में पेयजल की किल्लत को दूर कारने को कहा।

सभी नेताओं की नाराजगी देखने को मिली- मीटिंग में सांसद, विधायकों की नाराजगी भोपाल स्मार्ट सिटी पर देखने को मिलीं। उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में शिकायत की। स्मार्ट सिटी के सीईओ मीना भी मीटिंग में नहीं थे। इस कारण नाराजगी और भी बढ़ गई। सीईओ के गायब होने पर मंत्री काश्यप ने सख्त नाराजगी जताई।

स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे प्रभारी मंत्री- प्रभारी काश्यप ने कहा, भोपाल के विकास के कार्यों और योजनाओं को लेकर नया कीर्तिनाम बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में मीटिंग करेंगे। जिसमें स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे।

हर महीने मीटिंग करेंगे- मंत्री काश्यप ने बताया कि जल्द ही नगर निगम की मीटिंग करेंगे। जिसमें विकास कार्यों को लेकर बात की जाएगी। इस बैठक में मेट्रो समेत अन्य विषयों पर बात की है। अगले महीने से नियमित रूप से मीटिंग करेंगे। ताकि सभी प्रस्ताव पास हो सके। सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में गोवंश के लिए गोशाला और जलप्रदाय जैसे बिंदुओं पर भी बात की गई है।

दुष्कर्म जैसी घटना न हो, इसके प्रयास करेंगे- भोपाल के प्राइवेट स्कूल में बच्ची से रेप के मामले को लेकर मंत्री काश्यप ने कहा कि कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे से ऐसी घटना न हो, इसके लिए बड़े प्रयास किए जाएंगे।

नेताओं की नाराजगी के बाद सीईओ को नोटिस- मीटिंग में प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायकों की नाराजगी के बाद स्मार्ट सिटी के सीईओ मीना को कलेक्टर सिंह ने नोटिस दिया है। इसके साथ ही मंत्री ने स्मार्ट सिटी एडवाइजरी बोर्ड की एक अलग विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं।

सीईओ पर सबसे ज्यादा सांसद-विधायकों का गुस्सा फूटा- बताया जाता है कि मीटिंग में सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा सीईओ मीना को लेकर जमकर नाराज हुए। विधायक सबनानी ने भी नाराजगी जताई। इसके लिए मीटिंग में काफी देर तक हंगामा हुआ। कलेक्टर ने सीईओ को मीटिंग से ही कॉल लगाने की बात कही तो उन्हें विधायकों ने मना कर दिया। प्रभारी मंत्री ने भी मीटिंग से गायब रहने पर नाराजगी जताई।

जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर भी चिंता

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की और इन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल योजनाओं में निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

खेल मैदानों के लिए कलेक्टर लिखेंगे पत्र

सीएम राइज स्कूलों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि जिले के सभी सीएम राइज स्कूलों में खेल मैदानों का विस्तार किया जाए। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वे शिक्षा मंत्री को अतिरिक्त राशि आवंटन के लिए पत्र लिखें। मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत संजीवनी क्लीनिकों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी बैठक में दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराकर उनके माध्यम से क्लिनिकों का उद्घाटन कराया जाए।

इनकी समीक्षा की गई

बैठक में मंत्री काश्यप ने राजस्व महाअभियान, जल जीवन मिशन, पौधारोपण अभियान, सीएम राइज स्कूल, अमृत 2.0, मौसमी बीमारियां, निर्माण कार्य एवं समसामायिक विषयों की समीक्षा की। संबंधित विभाग का प्रजेंटेशन देकर जानकारी दी गई। बता दें कि इससे पहले प्रभारी मंत्री की चार मीटिंग स्थगित की गई थी। 30 अगस्त, 3 सितंबर, 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी मीटिंग होनी थी, लेकिन बाद में स्थगित हो गई थी।

संपादकीय

तिरूपति प्रसाद में मिलावट : कई सवाल

आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरूपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाने का गंभीर आरोप राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र और सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी के महासचिव नारा लोकेश ने लगाया है। इसका एक मकसद पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधना भी है। लेकिन जो आरोप लगाया गया है, वह बेहद गंभीर है और पूरे मामले की जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग करता है। क्योंकि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है। हाल में नारा लोकेश ने दावा किया कि पिछली सरकार (जगन मोहन रेड्डी) में प्रसाद के लड्डू के घी में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हुआ है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रदेश की पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि तिरुमला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। इस बात की पुष्टि हो गई है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। तेलुगू देशम पार्टी के प्रवक्ता अनम वेंकट रमना रेड्डी ने 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि गुजरात स्थित लाइवस्टॉक लैबोरेटरी, एनडीडीबी (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बोर्ड) के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड (काफ) को 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया था। लैब की रिपोर्ट सरकार को 16 जुलाई को मिली। इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। वाईएसआरसीपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्बा रेड्डी ने आरोप लगाया कि नायडू ने अपनी टिप्पणियों से पवित्र तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर रूप से नुक़सान पहुंचाया है। तिरुमाला प्रसादम के बारे में नायडू की टिप्पणी बेहद दुर्भावनापूर्ण है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाई एस शर्मिला ने कहा कि क्या मिठाई बनाने के लिए वास्तव में पशु के वसा का इस्तेमाल किया गया था, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए साथ ही सरकार इस मामले में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करे। भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि तिरुपति लड्डू प्रसादम में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत पर सीधा हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि तिरूपति बालाजी से श्रीराम मंदिर के प्रतिष्ठापना समारोह में 1 लाख लड्डू भेजे गए गए थे, वो भी शक के घेरे में हैं। यहां सवाल यह है कि अगर सचमुच प्रसाद में अपवित्र पदार्थों की मिलावट की गई है तो इसके पीछे कौन है? दूसरे, जो सेम्पल जांच के लिए एनडीडीबी लैब भेजा गया था, क्या उसी तरह किसी दूसरे सेम्पल की जांच किसी अन्य लैब में भी कराई गई थी ताकि आरोप की पुष्टि हो सके? गुजरात और केन्द्र में भाजपा की सरकार है और एनडीडीबी उसी के अधीन है। यह प्रसाद भी मंदिर की लैब में जांच के बाद ही वितरित किया जाता है। अगर प्रसाद में मिलावट हो रही थी तो फिर मंदिर की लैब में उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर पकड़ा गया तो क्या उसे दबाने की कोशिश हुई? कुल मिलाकर मामला गंभीर है और न केवल तिरूपति बल्कि सभी प्रमुख मंदिरों में बनने वाले प्रसादों के लिए शुद्धता के निश्चित और कड़े मापदंड तय करने की मांग करता है। गौरतलब है कि मंदिर में प्रसाद वहां के ब्राह्मण ही बनाते हैं और प्रतिदिन साढ़े 3 लाख लड्डू बनते हैं।

नजरिया

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

'एक देश एक चुनाव' अमृतकाल की अमृत उपलब्धि बने

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 'एक देश एक चुनाव' के अपने चुनौतीपूर्ण संकल्प को लागू करने की बात कहकर राजनीतिक चर्चा को गरमा दिया है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती एवं चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रासंगिक एवं कम खर्चीला बनाने के लिये 'एक देश एक चुनाव' पर चर्चा होती रही है। इसको लेकर भाजपा जिस तरह बेझिझक होकर तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा कि केंद्र को सहयोगी दलों का पूरा समर्थन मिल रहा। दो बड़े दलों में से एक जेडीयू ने मोदी के 'एक देश एक चुनाव' वाले इरादे पर सहमति जता दी है। कहा गया कि राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के भीतर इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार को लागू कराने को लेकर आशावादी है और उसके इस आशावाद में देश को एक नई दिशा मिल सकेगी। भारत की वर्तमान चुनावी प्रणाली में निहित कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा एक संभावित समाधान के रूप में उभरी है। शासन के सभी स्तरों- पंचायत, नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय- में एक साथ चुनाव कराने से लागत (खर्च)-प्रभावशीलता और प्रशासनिक दक्षता से लेकर बेहतर शासन और नीति निरंतरता तक कई लाभ मिल सकते हैं। यह नये भारत, सशक्त भारत एवं विकसित भारत के संकल्प को आकार देने का मुख्य आधार बन सकता है एवं आजादी के अमृतकाल की एक अमृत उपलब्धि बनकर सामने आ सकता है।

भले ही स्पष्ट बहुमत के अभाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की तीसरी पारी में बदलावकारी फैसले लेना उतना सहज नहीं रह गया है, जितना पहली-दूसरी पारी में नजर आता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी भी कमजोर नहीं है कि अपने चुनावी वायदों एवं विकासमूलक कार्ययोजनाओं को लागू न कर सके। नरेन्द्र मोदी जैसा साहसी एवं करिश्माई नेतृत्व है तो उसके द्वारा देशहित की योजनाओं में आने वाले अवरोध वह दूर कर ही लेंगे। एक दशक की विकासमूलक कार्यशैली के बाद अब भी भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। भले ही भाजपा-सरकार कई मुद्दों पर यू टर्न लेते हुए भी नजर आई। बहरहाल, लोकसभा में पहले के मुकाबले कमजोर स्थिति होने के बावजूद खुद को साहसिक निर्णय लेने वाली पार्टी के रूप में एक बार फिर अपने एक मुख्य एजेंडे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को आकार देने के लिये तत्पर हो गयी है। इसके लिए सरकार ने पक्ष-विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध किया था। निस्संदेह, एक राष्ट्र, एक चुनाव के लिये भाजपा द्वारा नई पहल किए जाने के निहितार्थ राजनीति से ज्यादा राष्ट्रहित में है।

निश्चय ही 'एक देश एक चुनाव' की योजना को लागू करना राजग के लिये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि इस बार विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत भी है और एकजुट भी है। इसमें दो राय नहीं कि यह बात तार्किक है कि एक

राष्ट्र, एक चुनाव का प्रयास शासन में सुनिश्चितता लाएगा। वहीं बार-बार के चुनाव खर्चीले होते हैं। दूसरे राज्य-दर-राज्य लंबी आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। साथ ही साथ शासन-प्रशासन व सुरक्षा बलों की ऊर्जा के क्षय के अलावा जनशक्ति का अनावश्यक व्यय होता है। विगत लोकसभा चुनावों में कुल सरकारी खर्च 6600 करोड़ रुपये आया था जो भारत जैसे विविधतापूर्ण विशाल देश को देखते हुए भले ही जायज कहा जाये, लेकिन बार-बार होने वाले चुनावों से होने वाले ऐसे भारी-भरकम खर्चे देश की अर्थ-व्यवस्था पर बोझ तो डालते ही है। भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भी महंगी होती चुनाव व्यवस्था है क्योंकि जब करोड़ों रुपये खर्च करके कोई विधानसभा या लोकसभा का प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनेगा तो वह विजयी होने के बाद सबसे पहले अपने भारी खर्च की भरपाई करने की कोशिश करेगा। अतः असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करने पर सभी राजनैतिक दलों में एक सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन पक्ष एवं विपक्ष को अपने राजनीतिक हितों की बजाय देशहित को सामने रखकर इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए। पारदर्शी व निष्पक्ष चुनाव के लिये एक साथ चुनावी मशीनरी तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता के यक्ष प्रश्न को भी सामने रखकर इस पर सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत हमेशा से राजनीतिक विचारधाराओं, विविध संस्कृतियों और विशाल आबादी का मिश्रण रहा है। हर गुजरते चुनाव चक्र के साथ, राष्ट्र लोकतांत्रिक उत्साह का महाकुंभ देखता है, जहाँ लाखों लोग अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हालाँकि, इस जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच, विभिन्न स्तरों-स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय-पर चुनावों के समन्वय को लेकर बहस ने हाल के वर्षों में काफी जोर पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक दशक के शासन एवं पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से किए गए अपने संबोधन में 'एक देश, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी चुनाव घोषणापत्र में उसने 'एक देश, एक चुनाव' को प्रमुख वादों के रूप में शामिल किया था।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। समिति ने राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के साथ परामर्श किया और संभावित अनुशंसाओं के साथ आम लोगो एवं न्यायविदों के विचार आमंत्रित किये। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा, विधि आयोग भी 2029 से एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। असल में बात सम्पूर्ण चुनावी व्यवस्था के सुधार की होनी चाहिए। मगर इसकी बात करते हुए सभी राजनैतिक दलों के सामने निजी हित एवं चुनाव जीतने का गणित सामने आ जाता है। भारत की असली विडम्बना यही है। जब भी सरकारी खर्चे से चुनाव कराने की बात होती है तो इस राह को अव्यावहारिक बता दिया जाता है। जबकि जर्मनी जैसे लोकतन्त्र में यह प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव एक साथ प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं, जबकि नगर निकाय चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित किये जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी कौंसिल और स्थानीय निकायों/नगर निकाय सभाओं के चुनाव एक निश्चित तिथि, यानी हर चौथे वर्ष सितंबर के दूसरे रविवार को आयोजित किये जाते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता एवं पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करने के लिये निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 पारित किया गया था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रथम चुनाव 7 मई 2015 को और उसके बाद हर पाँचवें वर्ष मई माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा।

जब दुनिया के अनेक देशों में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' की परम्परा सफलतापूर्वक संचालित हो रही है तो भारत में इसे लागू करने में इतने किन्तु-परन्तु क्यों है? देश में इसे लागू करने से सरकार कुछ-कुछ समय बाद चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन यानी विकास योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे समय एवं संसाधनों की भी बचत होगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा। इन सब स्थितियों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराये जाने पर क्षेत्रीय पार्टियों को होने वाले नुकसान एवं अन्य स्थितियों पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि एक आदर्श एवं सशक्त लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों के लिये समान अवसर उपलब्ध होना भी जरूरी है।

निर्मल रानी

लेखक स्तंभकार हैं।

असंगठित व विभाजित समाज यूं ही लुटता रहेगा

यदि आप रोड टैक्स अदा किये बिना वाहन चलायें तो आपका चालान होना निश्चित है। नगर पालिकाओं व नगर निगम को यदि आप नाले व सीवर सेवाओं के भुगतान समय से अदा न करें गृह कर का भुगतान निर्धारित समय पर न करें तो जुर्माना लगना लाज़िमी है। और अब तो थोड़े-थोड़े फ़ासले पर पड़ने वाले टोल बैरियर जनता से पैसे वसूलने के लिये लगाये गये हैं। हालांकि अभी तक टोल वसूलने का तर्क ही समझ में नहीं आया कि आख़िर जब सरकार किसी व्यक्ति के नया वाहन लेने के समय ही प्रत्येक वाहन से एक मुश्त मोटा रोड टैक्स वसूल कर लेती है उसके बाद क़दम क़दम पर टोल वसूली का क्या मतलब है ? और अगर प्रत्येक गाड़ी से जगह जगह टोल वसूलना ही है तो रोड टैक्स के नाम पर वसूल की जाने वाली मोटी रक़म वसूलने का मतलब क्या ? अभी पिछले दिनों हुई बारिश में नवनिर्मित सड़कों में गड्ढे पड़ते दिखाई दिये। अनेक वाहन उसमें धंसे हुये नज़र आये। कौन है इसका ज़िम्मेदार ? टैक्स अदा करने वाली जनता या टैक्स के नाम पर लूट व भ्रष्टाचार करने वाली सरकार व प्रशासन ? मगर सरकार सब कुछ मनमानी तरीक़े से कर रही है। और परेशानहाल आम लोगों की जेब किसी न किसी बहाने इसी तरह कटती रहती है।

सवाल यह है कि इस वसूली के बदले में सरकार जनता को वह सुविधाएं दे भी पाती है जिसके नाम पर जनता से पैसे वसूले जा रहे हैं ? जनता नाली व सीवर के नाम के बिल अदा करती है। जलापूर्ति विभाग पानी के पैसे लेता है। मगर जब नालियां व नाले जाम पड़े हों, दुर्गन्ध फैल रही हो। नियमित सफ़ाई न होती हो ? इसी तरह सीवरेज प्रणाली फ़ेल हो चुकी हो? जगह जगह सीवर के मेनहोल ओवर फ़्लो हो रहे हों? सड़कों व गलियों में इन ओवरफ़्लो सीवर की सड़ांध फैली हो ,नाले व नालियां भ्रष्टाचारयुक्त निर्माण के कारण टूटे पड़े हों,नालों का परवाह रुका पड़ा हो,इसके बावजूद यदि सरकार नाले व सीवर के बिल नियमित रूप से भेजती रहे तो जनता को क्या यह पूछने का हक़ नहीं कि यह किस बात के पैसे वसूले जा रहे हैं? इस भ्रष्टाचार,लापरवाही,ग़ैर ज़िम्मेदारी व सरकारी अनदेखी की क़ीमत जनता को बरसात में मोहल्ले कॉलोनी में जलभराव की स्थिति में अपने घरों के फ़र्नीचर व अन्य ज़रूरी व क़ीमती सामानों की बर्बादी से चुकानी पड़ती है। बाज़ार व दुकानें पानी से भर जाते हैं। दुकानदारों का भारी नुक़्सान भी होता है कारोबार भी ठप्प हो जाता है। कौन है इस दुर्व्यवस्था का ज़िम्मेदार ? आख़िर जनता को इस दुर्व्ययवस्था का भुगतान क्यों करना पड़े ?

सीवर के मेन होल के बैठ जाने पर गंदे व मलमूत्र युक्त कीचड़ भरे गड्ढों में स्कूटर साईकिल सवार गिर जाते हैं। उन्हें चोट लग जाते है। कई बार सड़कों के खुले मेन होल में गिरने से लोगों की मौत तक हो जाती है। परन्तु जनता की जान की कोई क़ीमत नहीं? जलापूर्ति विभाग पानी के पैसे तो ज़रूर लेता है परन्तु प्रायः काला विषैले व दुर्गन्धपूर्ण प्रदूषित जल की आपूर्ति होती है।

और अब इंतेहा तो यह हो चुकी है कि सत्ता समर्थक व शासन प्रशासन के लोगों ने इन बातों का ऐसा जवाब तैयार कर लिया है कि जनता का सवाल पूछना तो दूर उलटे उसी जनता को लाजवाब कर दिया जाता है। यानी अगर आप कहें कि हमारा घर मोहल्ला डूब रहा है तो जवाब मिलेगा कि अरे करोड़पतियों के सेक्टर डूबे हैं,पॉश कालोनियां डूबी हुई हैं। आप अपनी कॉलोनी मोहल्ला लिए बैठे हो? यदि आप अपनी दुकान या बाज़ार जलमग्न होने की बात करें तो जवाब मिलेगा कि डी सी ऑफ़िस, नगर निगम का दफ़्तर, बैंक मुख्यालय डूबा हुआ है आपको बाज़ार व अपनी दुकान की पड़ी है? यदि आप कहें कि बसअड्डा पानी से भरा हुआ है तो जवाब मिल सकता है कि रेल लाइनें पानी में डूबी हैं,हवाईअड्डा में पानी भर गया, हवाई अड्डे की छत बारिश में गिर गयी तो बस अड्डा क्या चीज़ है? यदि कहीं कोर्ट कचेहरी या अन्य भवन टपकता मिले तो जवाब मिल सकता है कि अरे भाई अयोध्या में भगवान राम का नवनिर्मित मंदिर टपक रहा है। जब भगवान का घर बारिश में सुरक्षित नहीं तो अन्य भवनों की बात ही क्या करनी?

गोया हालात अब ऐसे हो गए हैं कि हर साल अख़बारों व टीवी में जनता की इस तरह की परेशानियों की ख़बरें प्रकाशित प्रसारित होती रहती हैं परन्तु कोई कार्रवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि भुगतभोगी जनता असंगठित है और चतुर राजनीतिज्ञों द्वारा तरह तरह के वर्गों में विभाजित की जा चुकी है। जबकि परेशानी हर ख़ासो आम को उठानी पड़ती है। दूसरी तरफ़ इस दुर्व्यवस्था का ज़िम्मेदार वर्ग चाहे वह मंत्री,सांसद ,विधायक हो ,प्रशासनिक व स्थानीय निकाय के अधिकारी हों या फिर उनसे जुड़ा ठेकेदार तब्क़ा यह सभी संगठित होकर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। और आम लोग ग़रीब अमीरधनाढ्य,अभिजात, धर्म-जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, दलीय राजनीति जैसे अनेक वर्गों में बंटे हुये हैं। समाज के इसी विभाजन का लाभ वह संगठित वर्ग उठता है जो जनता के टैक्स के पैसों को तो विकास के नाम पर मिलकर लूटता खाता है परन्तु उसी जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता जो देश की अनेक आधारभूत सुविधाओं के लिये टैक्स तो अदा करती है परन्तु वह सुविधाएँ उसे मिल नहीं पातीं। कहना ग़लत नहीं होगा कि जब तक हमारा समाज असंगठित व विभाजित रहेगा इसी तरह संगठित सत्ताधारियों व शासकों द्वारा हमेशा असुविधाओं का सामना करता रहेगा तथा यूँही लुटता रहेगा।

शोषण के खिलाफ अब बोलती हैं किशोरियां

मुद्दा

रजनी प्रकाश व सोनम कुमारी

स्कूल जाते थे तो कुछ लड़के कभी कभी कमेंट करते रहते थे. एक दिन हम लोग अच्छे से सुना दिए, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर उनको बोलने लगे. आसपास लोग भी जमा हो गए थे. सब मिलकर उन लड़कों को खूब डांटे. उसके बाद से आज तक कोई लड़का कमेंट नहीं करता है. हम लोग अब आराम से स्कूल जाते हैं. असल में ई लड़का लोगों को लगा कि हम लड़की सब कमज़ोर हैं. हम लोग डर से कुछ नहीं बोलेंगे. लेकिन अब उन लोगों को समझ में आ गया कि ई लड़की सब मज़बूत है. 16 वर्षीय प्रीति जब अपनी बात रख रही थी तो उसमें गज़ब का उत्साह था. उसका हाव भाव बता रहा था कि वह इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं और किशोरियों के खिलाफ होने वाली हिंसा को न केवल पहचानती है बल्कि उसका बखूबी मुकाबला करना भी जानती है।

प्रीति बिहार की राजधानी पटना स्थित स्लम बस्ती 'बघेरा मोहल्ला' की रहने वाली है. दसवीं की इस छात्रा के पिता ऑटो ड्राइवर और मां घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है. प्रीति कहती है कि पहले हम लोग उन लड़कों के कमेंट को नज़रअंदाज़ कर देते थे कि कौन इनके मुंह लगे. घर में भी डर से नहीं बताते थे कि कहीं हमीं लोग का पढ़ाई न छुड़वा दिया जाए. लेकिन जब उनका कमेंट दिन-ब-दिन बढ़ने लगा तो हिम्मत करके हम लोग जवाब दिए. प्रीति के साथ स्कूल जाने वाली उसकी दोस्त अर्चना (नाम बदला हुआ) कहती है कि 'उस दिन हम लोग सोच लिए थे कि आज इन लड़कों को जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो इनका मनोबल बढ़ता जाएगा. अगर लड़का लोग ज़रा भी बोलता न, तो हम लोग सीधा पुलिस बुला लेते. हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देते. फिर जो होता देखा जाता.' वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि 'जब हम लोग गलत नहीं हैं तो काहे डरें. डर कर रहते हैं इसीलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है.' वह बताती है कि हमारे स्कूल में महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, हालांकि हमें इसके बारे में कभी बताया नहीं गया, लेकिन हम उस नंबर की महत्ता के बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित बघेरा मोहल्ला पटना के गर्दनीबाग इलाके में स्थित है. यह बस्ती पटना हवाई अड्डे से महज 2 किमी दूर और बिहार हज भवन के ठीक पीछे आबाद है. ऐतिहासिक शाह गड्डी मस्जिद, (जिसे स्थानीय लोग सिगड़ी मस्जिद के नाम से जानते हैं), से भी इस बस्ती की पहचान है. इस बस्ती तक पहुंचने के लिए आपको एक खतरनाक नाला के ऊपर बना लकड़ी के एक कमजोर और चरमराते पुल से होकर गुजरना होगा. यहां रहने वाली 80 वर्षीय रुकमणी देवी बताती हैं कि वह इस बस्ती में पिछले 40 सालों से रह रही हैं. इस बस्ती में करीब 250-300 घर हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 700 के करीब है. उनके अनुसार 1997 में सरकार ने इस बस्ती को स्लम क्षेत्र घोषित किया था. यहां लगभग 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के लोग आबाद हैं. जिनका मुख्य कार्य मजदूरी और ऑटो रिक्शा चलाना है. रुकमणी देवी की पहचान क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है. जो इस बस्ती की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती रही हैं।

वह कहती हैं कि 'शहर के बीच में होने के बावजूद शैक्षणिक रूप से यह स्लम बस्ती अभी भी पिछड़ा हुआ है. अधिकतर लड़के 12वीं के बाद पिता के साथ उनके कामों से जुड़ जाते हैं. वहीं लड़कियों की 12वीं के बाद या तो शादी हो जाती है या फिर उनकी पढ़ाई छुड़वा कर घर के कामों में लगा दी जाती हैं. अपने अनुभवों के आधार पर वह कहती हैं कि 'पहले से अब बहुत कुछ बदल गया है. अब लड़कियां डरने की जगह निडर होकर जवाब देने लगी हैं. वह पुरुषों द्वारा बनाये गए समाज के उसूलों को चुनौती देने लगी हैं. पहले उन्हें चुप रहना सिखाया जाता था. सर झुका कर स्कूल और कॉलेज आने जाने की हिदायत दी जाती थी. लेकिन पहले की तरह अब ऐसा कम होता है. अब किशोरियां किसी कमेंट का जवाब देने का हौसला रखती हैं. हालांकि उनका मानना है कि अभी भी यह बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिलता है. कई जगह लड़कियों के साथ शारीरिक या मानसिक हिंसा की ख़बरें आती रहती हैं. जिसे समाप्त करने की ज़रूरत है.'

रुकमणी देवी का विचार है कि सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम चलाये जाते हैं. इसके अतिरिक्त 24 घंटे महिला सुरक्षा हेल्पलाइन भी संचालित की जाती है. लेकिन महिलाओं और किशोरियों को इसकी बहुत कम जानकारी होती है. जिसकी वजह से वह इसका उपयोग नहीं कर पाती हैं. इसके लिए स्कूल और कॉलेज में बताने की ज़रूरत है. वह कहती हैं कि कई बार सामाजिक दबावों की वजह से परिवार भी पुलिस थानों के चक्कर से बचने के लिए छेड़छाड़ या कमेंट करने वाले लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहते हैं. जो गलत है, इससे किशोरी पर मानसिक दबाव पड़ता है. उनकी यह बात इसी बस्ती से महज़ तीन किमी दूर एक अन्य स्लम बस्ती अदालतगंज में सच होती नज़र आती है. जहां रहने वाली अधिकतर महिलाओं और किशोरियों को महिला हेल्पलाइन नंबर और इसके उपयोग के बारे में बहुत कम जानकारियां थीं. यहां रहने वाली 20 वर्षीय पूजा कहती है कि उसने सरकार द्वारा संचालित महिला हेल्पलाइन के बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन उसे इसका नंबर तक पता नहीं है. वह कहती है कि कई बार लड़कों के कमेंट से उसे मानसिक पीड़ा होती है लेकिन वह सिर्फ इस डर से उनका जवाब नहीं देती है कि कहीं उसका घर से निकलना बंद न करवा दिया जाए।

पटना सचिवालय के करीब आबाद यह स्लम बस्ती तीन मोहल्ले अदालतगंज, ईख मोहल्ला और ड्राइवर कॉलोनी में बंटा हुआ है. जिसकी कुल आबादी लगभग एक हज़ार के आसपास है. यहां करीब 60 प्रतिशत ओबीसी और 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के लोग निवास करते हैं. यहां रहने वाली 21 वर्षीय पूनम, 18 वर्षीय आरती, 15 वर्षीय प्रिया और ज्योति कहती है कि उन्हें अक्सर स्कूल या कॉलेज आते जाते लड़कों द्वारा किया जाने वाला कमेंट सुनना पड़ता है. लेकिन वह उनका जवाब देने की जगह इसे नज़रअंदाज़ करने पर मजबूर हैं. यह लड़कियां कहती हैं कि उन्हें महिला हेल्पलाइन नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं है. वह इसके प्रयोग का तरीका भी नहीं जानती हैं. वह कहती हैं कि इसके लिए स्कूल और कॉलेज में विशेष अभियान चला कर लड़कियों को जागरूक किया जाना चाहिए. उन्हें इसकी उपयोगिता और महत्ता के बारे में बताना चाहिए ताकि लड़कियां इसका उपयोग कर कमेंट करने वालों के खिलाफ कारवाई कर सकें. वह कहती हैं कि इस प्रकार के कमेंट से लड़कियां मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं. उन पर मानसिक दबाव पड़ता है जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है. उनका मानना है कि यह उनके साथ एक प्रकार से हिंसा है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. प्रदीप मिश्र

(व्यंग्यकार एवं लेखक)

खेती- बबूल और बाबाओं की....

सोचता हूँ बबूल की खेती करने लगूँ। बाजार में आम से अधिक बबूल की डिमांड है। पुरानी कहावत बदल गई है कि,'बोया पेड़ आम का, बबूल कहाँ से होय...।'

बबूल की अनेक प्रजातियाँ होतीं हैं, लेकिन बाबा प्रजाति के बबूल को सर्वाधिक पसंद किया जाता है। बबूल और बाबा के स्वबभाव समान हैं। राशियाँ भी एक हैं। दोनों में फर्क यह होता है कि सामान्य बबूल के काँटे चुभने पर कम कष्ट देता है। दर्द देने वाले तमाम उत्पादों की खेती लाभप्रद हो गई है, इसलिए मैंने दोनों की खेती करने की सोच रहा हूँ- बबूल या बाबा, एक तो ऊग ही जाएगा। बबूल ऊगा तो कम फायदा होगा और बाबा ऊग आया तो,मेरे पौ बारह हो जाएंगे।

शुरूआत करने से पहले मैंने जानकारी के लिए इस खेती के जानकारों से कुछ सवाल पूछे हैं,

1. सामान्य बबूल और बाबा बबूल में क्यो समानता होती है?
2. बबूल के काँटे, बाबाओं की तरह और बाबा, बबूल के काँटों की तरह नजर आते हैं या नहीं?
3. बाबाओं में बबूल के काँटे कब नजर आते हैं, जेल जाने से पहले या बाद?
4. जिस खेत में इनकी खेती होती है उसे क्या कहते हैं, गुरुगृह, आश्रम, डेरा, या और कुछ?
5. खेत में कार्य करने वाले बँधुआ मजदूरों को किस नाम से पुकारा जाता हैज्भक्त, मजदूर, चेले या अनुयायी?
6. क्या यह सच है कि बबूलों और बाबाओं के पेड़, तेजी से तब बढ़ते हैं, जब उनकी देखभाल सुंदर लड़कियाँ करतीं हैं?
7. बबूल के पेड़ पर आम फलने और बाबा के सद्चरित्र होने की उम्मीदें, कितनी फलीभूत होतीं हैं?
8. 'एक बाबा, एक लाख सामान्य बबूल के बराबर होता है, इसलिए हमारे जननायक, लाख बबूल रोपने की जगह, एक बाबा रोप लेते हैं।' इस कथन पर अपनी राय दें।
9. मुल्क की बेहतरी के लिए सबसे जरुरी क्या है- बाबानुमा बबूल या बबूलनुमा बाबा या फिर दोनों?

जानकारों के उत्तर का मुझे इंतजार है।

विश्व अल्जाइमर जागरूकता दिवस पर विशेष

बढ़ती उम्र में अकेलापन और अल्जाइमर : एक गंभीर चुनौती

स्मिता कुमारी

लेखिका सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की डायरेक्टर एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक हैं।

बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी के लिए बाहर भेजते समय मां-बाप जिस व्याकुलता से अपने बच्चों के लिए हर सामान पैक कर देना चाहते हैं. बस वही थोड़ी-सी व्याकुलता बच्चों में भी चाहिए. क्योंकि उनके पीछे उनके मां-बाप अपने गांव-समाज में अकेले छूट रहे हैं. या अकेलापन के घुप अंधेरे में समाए जा रहे हैं. अकेले जीवन जीना उतना कठिन नहीं है, जितना अकेलापन में जीना. परिवार को बेहतर सुख-सुविधा देने के नाम पर दिन-रात कड़ी मेहनत करने वाले वयस्कों को थोड़ा ध्यान इस बात पर भी केंद्रित करने की जरूरत है कि कहीं वह इस भागमभाग की जिंदगी में अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भावनात्मक दूरी तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं बढ़ती उम्र में खुद के लिए अकेलापन को बुलावा तो नहीं दे रहे हैं? यह भी सोचने की जरुरत है कि अपने गांव या शहर को छोड़, बच्चों के साथ रहने वाले बुजुर्ग अकेले जीवन व्यतीत करने से तो बच गए, मगर क्या उनके बच्चों ने उनके अकेलेपन से बचने के लिए कुछ गतिविधियों को तय किया है?

साल 2012 से प्रति वर्ष पूरी दुनिया में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है. अल्जाइमर की पहचान सबसे पहले एक जर्मन मनोचिकित्सक एलोइस अल्जाइमर ने साल 1901 में इलाज के दौरान अपनी 50 वर्षीय महिला रोगी में इस बीमारी की पहचान की थी. इसलिए इस बीमारी का नाम उनके नाम रखा गया. यह बीमारी न्यूरॉन्स के निष्क्रिय या नष्ट होने से होती है जिस कारण मस्तिष्क को कई सूचनाएं सही रूप में प्राप्त नहीं होती, जिससे यह बीमारी होती है. इसके अलावा हेड इंजरी, वायरल इंफेक्शन, डाउन सिंड्रोम और ब्रेन स्ट्रोक में भी अल्जाइमर की स्थिति पैदा हो सकती है. सबसे गंभीर विषय यह है कि भारत में इसके मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं. फिर भी इसके प्रति समाज में जागरूकता बेहद ही कम है. भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) के डेटा के अनुसार 60 साल से अधिक उम्र के 88 लाख भारतीय अल्जाइमर से पीड़ित हैं. वहीं दुनिया भर में लगभग 5.7 करोड़ से अधिक लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में सोशल जीनोमिक्स कोर प्रयोगशाला के निदेशक, डॉ. स्टीव कोल अपने रिसर्च में कहते हैं, 'अकेलापन अन्य बीमारियों के लिए उर्वरक का काम करता है. अकेलेपन मस्तिष्क में सूजन को बढ़ावा दे सकती है जिससे अल्जाइमर रोग हो सकता है.'

अल्जाइमर में सोचने-समझने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नई और वर्तमान चीजों को याद रखने में कठिनाई, दिमाग का पहले की तुलना में कम काम करना, भटकाव, भ्रम की स्थिति, सामान्य चीजे भूल जाना, सुधबुध खोना, तर्क या गणित के सामान्य क्रिया करने में समस्या महसूस करना होता है. इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार और जीवन दोनों पर पड़ता है. व्यक्ति कई बार आक्रामक भी हो जाता है, खुद की देखभाल नहीं रख पाता. मिज़ाज में बदलाव, अकेलापन, असंतुष्ट रहने लगता है. धीरे-धीरे उसकी सामाजिक दूरी लोगों से काफी बढ़ जाती है. वह कई बार अपनों पर विश्वास भी नहीं करता है. इस बीमारी से रोगी और रोगी के परिवार को काफी मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है. यह एक बार होने के बाद इलाज से पूर्णतः ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सही समय पर इलाज से इसके प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

कैसे बचें?

- सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लोगों की दिनचर्या को इस तरह प्लान करें जिसमें सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, गतिविधियां सम्मिलित हों. शारीरिक व्यायाम के साथ मस्तिष्क का व्यायाम (ब्रेन जिम) भी जरूरी है.
- परिवार के साथ थोड़ा समय बितायें, उस समय में एक-दूसरे को सुनने और कहने का मौका दें, मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग उस समय करने से बचें.
- अगर घर के बुजुर्ग अपने घर में या आपके पास अकेले रहते हों तो उनको उनके मनमुताबिक शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधि से जोड़ें और रोज थोड़ा समय निकाल उनके दिनचर्या के बारे में पूछें, उनके गतिविधियों को सराहें, उन्हें उत्साहित करें. उन्हें सामाजिक गतिविधियों से जोड़े, बुजुर्गों और बच्चों के बीच तालमेल बिठाने के लिए योजना बनाएं. कहानियां, क्रॉस गेम, पहेलियां आदि गतिविधियों में शामिल करें.
- गाड़ी नियंत्रण में चलायें, हेलमेट और सीटबेल्ट का उपयोग करें, नशा का सेवन करने से बचें,
- खान-पान का ध्यान रखें, संतुलित एवं पौष्टिक आहार जैसे पत्तेदार सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मछली का सेवन करें. भरपूर पानी का सेवन करें, शुद्ध हवा में टहलने जायें जिससे मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिल सके.
- तनाव से बचें, बीपी, शुगर, कॉलेस्ट्रॉल आदि को नियंत्रित रखें. समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक समस्या होने पर या अल्जाइमर के लक्षण दिखने पर तत्काल न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकेट्रिस्ट और मनोचिकित्सक से सम्पर्क करें. इसके लिए डॉक्टर के सलाह से दवा लेने के साथ मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से रोगी और उनके परिवार के तनाव को कम करने एवं जीवनशैली सुधार करने में मदद किया जा सकता है.

(अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस पर विशेष)

शांति की संस्कृति का मूल आधार प्रेम है

चित्रा माली

सहायक प्रोफेसर गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। 1981 में कोस्टारिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे बुधवार को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा । ताकि समूचा विश्व एक दिन शांति के लिए समर्पित रहे और समूचे विश्व में कहीं भी इस दिन युद्ध की विभीषिका को न झेलना पड़े। 2001 में ब्रिटेन के द्वारा एक नया प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में प्रस्तुत किया गया । जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के लिए एक दिन विशेष निश्चित करने की मांग की गई थी और इस दिन को वैश्विक अयुद्ध दिवस के रूप में मनाए जाने की बात भी कही गई । इस प्रस्ताव के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने वर्ष 2002 में प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की । संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में शांति घंटा (Peace Bell) बजाकर इस दिन का आरंभ किया जाता है । इस पीस बेल का निर्माण सभी महाद्वीप के बच्चों के द्वारा एकत्रित और समर्पित सिक्कों को गलाकर किया गया है । पीस बेल के एक तरफ 'लांग लिव एबसोलुट पीस' लिखा है । वर्ष 2005 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने इस दिन को चिह्नित करने के लिए पूरे विश्व में 22 घंटे के युद्धविराम और इस दिन अहिंसा के पालन का आह्वान किया था। इसी वर्ष शांति की संस्कृति की पहल के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया गया जिसमें 46 देशों में घटित घटनाओं का वर्णन किया गया था ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके । वर्ष 2006 में यूनाइटेड किंगडम ने ग्रेटर मैनचेस्टर के रोशडेल में 'शांति मार्च '(पीस परेड) का आयोजन किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति के लिए कार्य करने वाले और समूचे विश्व के नागरिकों से शांति प्राप्त करने के तरीकों पर विचार करने और शांति विचारों, शांति कार्यक्रमों को संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों पर जोर दिया ।

वर्ष 2007 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने 21 सितंबर को 24 घंटे के लिए शत्रुता समाप्त करने और दुनिया भर में एक मिनट का मौन रखने का आह्वान किया था । वर्ष 2009 अंतरराष्ट्रीय सुलह वर्ष घोषित किया गया । इसमें अंतर्राष्ट्रीय विवादों और परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया जो शांति भंग कर सकते हैं, और सहिष्णुता का अभ्यास करना और अच्छे पड़ोसियों के रूप में एक दूसरे के साथ शांति से रहना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों और मानवीय मुद्दों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना शामिल किया गया था । राष्ट्रों के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार की आवश्यकता के लिए नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए गए । 2010 से प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के लिए वैश्विक परिदृश्य के आधार पर एक थीम का निर्धारण किया जाता है । वर्ष 2010 में 'शांति और विकास के लिए युवा' थीम रखी गई । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व भर के उन युवाओं की कहानियों को तलाशा गया जो शांति के लिए काम कर रहे थे । इस वर्ष अभियान का नारा था शांति = भविष्य, गणित आसान है ।

शांति और लोकतंत्र- अपनी आवाज़ बुलंद करें थीम रखी गई । इस वर्ष दुनिया भर में कई संगठनों ने शांति दिवस के लिए कार्यक्रम आयोजित किए । जिसमें संगीत समारोह, वैश्विक कॉमेडी क्लब,शांति कबूतर, प्रार्थना सभाएं शांति सम्मेलन व सेमिनार किए गए । पीस वन डे,वाइज़र और कल्चर ऑफ़ पीस जैसे संगठन वर्षों से शांति दिवस के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं । वर्ष 2012 में 'टिकाऊ भविष्य के लिए टिकाऊ शांति 'थीम रखी गई । जो सभी देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को याद दिलाती है और शांति के आदर्शों को मजबूत करती है । वर्ष 2013 में 'शांति शिक्षा पर ध्यान' थीम रखी गई । युक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने शांति को बढ़ावा देने और शांति की संस्कृति को विकसित करने के साधन के रूप में शांति शिक्षा की आवश्यता पर जोर दिया ।

वर्ष 2014 में 'शांति का अधिकार 'थीम रखी गई । जो लोगों के शांति के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है । क्योंकि शांति और शांति के अधिकार को बढ़ावा देना सभी मानव अधिकारों के लिए आवश्यक है। वर्ष 2015 में शांति के लिए साझेदारी और सभी के लिए सम्मान थीम रखी गई । वर्ष 2016 में सतत विकास लक्ष्य: शांति के लिए आधारशिला थीम रखी गई । वर्ष 2017 में शांति के लिए एक साथः सभी के लिए सम्मान, सुरक्षा और गरिमा थीम रखी गई । यह थीम TOGETHER वैश्विक अभियान पर आधारित थी जो बेहतर जीवन की तलाश में अपने घरों से बेघर और अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश सभी लोगों के लिए सम्मान, सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा देती है । वर्ष 2018 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 70 वर्षों के आधार पर थीम का निर्धारण किया गया और शांति का अधिकार - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा रखी गई । वर्ष 2019 में शांति के लिए जलवायु कार्यवाही थीम रखी गई और संयुक्त राष्ट्र ने सभी राष्ट्रों से जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को रोकने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। वर्ष 2020 में कोविड-19 के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक साथ शांति को आकार देना थीम रखी गई थी क्योंकि कोविड-19 ने हमारी पूरी दुनिया को बदल डाला है और हमें याद दिलाया है कि विश्व के एक हिस्से में जो कुछ भी होता है, उसका असर विश्व के हर व्यक्ति पर पड़ता है। वर्ष 2021 में समतापूर्ण और टिकाऊ विश्व के लिए बेहतर ढंग से उबरना थीम रखी गई । वर्ष 2022 में नस्लवाद खत्म करें, शांति कायम करें थीम रखी गई । वर्ष 2023 में शांति के लिए कार्य वैश्विक लक्ष्य (GlobalGoals) के लिए हमारी महत्वाकांक्षा थीम रखी गई थी । प्रत्येक वर्ष की थीम समूचे विश्व में शांति उत्सवों और गतिविधियों के लिए प्रेरणा का काम करती है तथा वैश्विक नागरिकों को विविध तरीकों से शांति के लिए चिंतन,मनन व प्रेरित करने और उसका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है । इस वर्ष की थीम शांति की संस्कृति का विकास है।

जो यूनेस्को की इस मूलभूत मान्यता से प्रेरित है कि युद्ध पहले मनुष्य के मन में शुरू होते हैं, इसलिए शांति की रक्षा का निर्माण भी मनुष्य के मन से ही होना चाहिए । शांति की संस्कृति को विकसित करने का प्रयास टॉलस्टॉय, थोरो और महात्मा गांधी ने भी किया था। जिनका स्पष्ट मत था कि शांतिपूर्ण समाज व्यवस्था के लिए शांतिपूर्ण व्यक्ति का होना आवश्यक है और शांतिपूर्ण समाज व व्यक्ति के विकास के लिए शांति की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है जो शांति की संस्कृति से ही विकसित हो सकती है। वैश्विक परिदृश्य में शांति का अभिप्राय युद्ध या किसी तरह के हिंसक संघर्ष का अभाव माना जाता है लेकिन जोहान गालटुंग जो शांति अध्ययन के संस्थापक माने जाते हैं उनके अनुसार शांति का यह अर्थ नकारात्मक है । आमतौर पर शांति को नकारात्मक रूपों में ही समझा और महसूस किया जाता रहा है । शांति की समग्रता को स्पष्ट करते हुए गालटुंग ने कहा है कि जब हम शांति के बारे में चर्चा या विचार विमर्श करते हैं तो इसका आशय इतना ही नहीं है कि शांति केवल राष्ट्रों के बीच में ही हो;बल्कि,शांति को समाज की रग-रग में,मानव जातियों में और यहां तक कि प्रकृति में भी व्याप्त होना चाहिए । गालटुंग द्वारा प्रतिपादित शांति की समग्र परिभाषा से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि शांति को छोटे छोटे अंशों में न देखकर समग्रता में देखा जाना आवश्यक है। शांति की इस समग्र अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की प्रत्येक वर्ष की थीम में देखा जा सकता है जो लगातार वैश्विक स्तर पर शांति निर्मित करने में अग्रसर है । अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस को मनाए जाने के औचित्य को गांधी के इन शब्दों से भी समर्थन मिलता है दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं, यह बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल पर नहीं है अपितु सत्य,दया या आत्मबल पर है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है । इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है ।

व्यक्तिगत शांति से ही विश्व शांति का मार्ग खुलता है

आलेख

डॉ. लोकेन्द्रसिंह कोट

बचपन छोड़कर जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे-वैसे हमारे अंदर तनाव के साथ बड़ी मात्रा में अशांति घर कर जाती है। कहाँ हम नवजात थे तब चार सौ बार मुस्कुराते थे और थोड़े बड़े क्या हुए, यह मुस्कुराहट बिरले हो जाती है। कुछ तो ऐसा है जो हमसे जुदा हो जाता है और हम अशांत हो जाते हैं। इसके बाद शांति की खोज में फिर इधर से उधर भटकते हैं। भोजन की तरह ही शांति भी हमारी अनिवार्य आवश्यकता है लेकिन इसका पता तभी चलता है जब हम कोई बीमारी से ग्रसित हो चुके होते हैं। अशांत मन कभी भी सही से कार्य नहीं निष्पादित कर सकता है और न ही सही निर्णय ले पाता है। इसका सीधा असर हमारी कार्यशैली पर पड़ता है, हमारे संबंधों पर पड़ता है और विचारों में आई विकृति समाज को भी कहीं न कहीं प्रभावित करती है। एक अकेला अशांत व्यक्ति पूरे परिवार के साथ आस-पास के वातावरण को भी अशांत कर सकता है और जब समाज में ज्यादातर मानव इससे पीड़ित हों तो इसका असर पूरे समाज और राष्ट्र पर भी पड़ता है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों में विवेक, संयम, धेर्य रहा ही नहीं है और ज्यादातर समस्याओं की जड़ में इन्ही की कमी बड़ी वजह बन कर उभर रही है।

सभी दूर विश्व शांति की बात की जाती है लेकिन व्यक्तिगत शांति की बाद को वो स्थान नहीं दिया जाता है। वास्तव में विश्व शांति के पहले व्यक्तिगत शांति होगी तभी तो वह सामूहिक चेतना बन कर शांति की ओर विश्व प्रशस्त हो सकेगा। जब हम सुबह उठते हैं और रेडियो सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो हमें एक ही दुखद खबर सुनने को मिलती हैः हिंसा, अपराध, युद्ध और आपदाएँ। मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं आता जब कहीं कोई भयानक घटना घटित होने की खबर न आई हो। आज के आधुनिक समय में भी यह स्पष्ट है कि किसी का कीमती जीवन सुरक्षित नहीं है। किसी भी पिछली पीढ़ी को इतनी बुरी खबरें नहीं सुननी पड़ी जितनी आज हमें सुननी पड़ रही हैं; भय और तनाव के बारे में यह निरंतर जागरूकता किसी भी संवेदनशील और दयालु व्यक्ति को हमारी आधुनिक दुनिया की प्रगति पर गंभीरता से सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। अक्सर जिसे हम विकास कहते हैं उसी विकसित देशों में अशांति की समस्या सबसे ज्यादा है। हमारी विकास की परिभाषाओं पर फिर से नजर डालने की आज जरूरत है। हमारा विकास भौतिक समृद्धि तो ला रहा है लेकिन मानसिक रूप से कुछ देने में असमर्थ हो रहा है। इस ओर हमारा ध्यान कब जाएगा यही मूल प्रश्न है। व्यक्तिगत स्तर की अशांति सामूहिक स्तर पर होते हुए देशों का प्रतिनिधित्व करने लगती है और युद्ध की विभिषिकाएँ देखना हमारा भाग्य हो गया है। ऐसा विकास जो हमें शांति नहीं दे सके, खुशी नहीं दे सके उस विकास पर विचार करना आज की महती आवश्यकता है।

हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी प्रगति और विकास में कुछ गंभीर गड़बड़ी होनी चाहिए और यदि हम समय रहते इसे नहीं रोकते हैं तो मानवता के भविष्य के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कोई भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिलकुल खिलाफ नहीं है, उसने मानव जाति के समग्र अनुभव में, हमारे भौतिक सुख और कल्याण में और जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसकी हमारी बेहतर समझ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन यदि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक जोर देते हैं तो हम मानवीय ज्ञान और समझ के उन पहलुओं से दूर हो सकते हैं जो ईमानदारी और परोपकारिता की आकांक्षा रखते हैं। जहाँ भावनाओं का स्थान होना चाहिये वहाँ सिर्फ मशीनीकृत इच्छाएँ होंगी तो तनाव, अशांति तो बढ़ना ही है। भावनाएँ हटा दी जाए तो सब कुछ मशीनी होने का आभास होने लगता है और मन अवसाद या वितृष्णा से भर सकता है। हमारा मन का अधिकांश संचालन भावनाएँ ही करती हैं और मषीन के लगातार उपयोग से भावनाएँ जड़ हो सकती हैं जिससे मन को मिलने वाली खुराक खत्म या कम हो जाएगी। आज यूरोप इसी भावनात्मक मकड़जाल में उलझा हुआ है। विकसित देश का तमगा हासिल करने के साथ हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक अवरोध या बीमारी से ग्रसित है। मषीन की तरह सब कुछ कार्य करना हमारी सारी संवेदनशीलता भी छीन सकता है। तमाम चमक-दमक के बावजूद हर किसी को वहाँ शांति की तलाश है।

मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में शांति है लेकिन समय के चलते इस पर कम ही ध्यान दिया गया और आज हमारे सामने हालात खराब हैं। हम सभी यह भी जानते हैं कि भारत जैसे देश में शांति की वकालात सदियों से हमारी संस्कृति करती आई है और आध्यात्म उसी का हिस्सा है। योग,ध्यान,प्राणायाम आदि जैसी बातों का उल्लेख हमारे मूल अस्तित्व में रहा है। आज भी विश्व भर से शाति का पाठ पढ़ने भारत ही आते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हालांकि अपार भौतिक सुख-सुविधाएँ पैदा करने में सक्षम हैं,लेकिन सदियों पुराने आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों की जगह नहीं ले सकते हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर विश्व सभ्यता को आकार दिया है, जैसा कि हम आज जानते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व भौतिक लाभ से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी बुनियादी मानवीय समस्याएँ बनी हुई हैं] हम अभी भी पीड़ा, भय और तनाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए एक ओर भौतिक विकास और दूसरी ओर आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों के विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करना ही तर्कसंगत है। इस महान समायोजन को लाने के लिए हमें अपने मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

विश्व शांति की बात यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से आज हम जिन अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं और उन्हें स्वीकार करके उनका सामना समभाव से करना चाहिए। हालांकि ज्यादातर समस्याएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं। जल, पर्यावरण भी ऐसे पक्ष हैं जिन पर एकमत होना आवश्यक है जो विश्व शांति के लिए भी आवश्यक हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध जल के लिए ही होगा, ऐसे में यह और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। ऐसी ही एक समस्या विचारधाराओं के टकराव से उत्पन्न होती है, चाहे वह राजनीतिक हो या धार्मिक, जब लोग तुच्छ उद्देश्यों के लिए एक.दूसरे से लड़ते हैं, और उस बुनियादी मानवता को भूल जाते हैं जो हमें एक मानव परिवार के रूप में एक साथ बांधती है। हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया के विभिन्न धर्म, विचारधाराएँ और राजनीतिक व्यवस्थाएँ मनुष्यों को खुशी प्राप्त करने के लिए हैं। हमें इस मूलभूत लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और कभी भी हमें साधनों को साध्य से ऊपर नहीं रखना चाहिए, पदार्थ और विचारधारा पर मानवता की सर्वोच्चता हमेशा बनाए रखी जानी चाहिए।

अब तक मानव जाति वास्तव में, हमारे ग्रह पर सभी जीवित प्राणियों के सामने सबसे बड़ा खतरा परमाणु विनाश का खतरा है। इस खतरे के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पर पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता और आपसी समझदारी भी उतनी ही आवश्यक है। सभी को पता है कि परमाणु युद्ध की स्थिति में कोई विजेता नहीं होगा क्योंकि कोई जीवित नहीं बचेगा! क्या इस तरह के अमानवीय और निर्दयी विनाश के बारे में सोचना ही डरावना नहीं है, और क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि जब हम कारण जानते हैं और ऐसा करने के लिए हमारे पास समय और साधन दोनों हैं तो हमें अपने विनाश के कारण को स्वयं ही हटा देना चाहिए, अक्सर हम अपनी समस्याओं पर काबू नहीं पा पाते हैं क्योंकि या तो हम कारण नहीं जानते हैं या, अगर हम इसे समझते हैं तो हमारे पास इसे दूर करने के साधन नहीं होते हैं। लेकिन परमाणु के संबंध में ऐसा नहीं है।

आध्यात्मिक विकास का एक और परिणाम, जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में सबसे अधिक उपयोगी है, यह है कि यह शांति और मन की उपस्थिति देता है। हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, जिससे कई कठिनाइयाँ आती हैं। जब शांत और स्पष्ट मन से सामना किया जाता है, तो समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। इसके बजाय, जब हम घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं, तो हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। हमारे दिमाग अंधे हो जाते हैं और उन उग्र क्षणों में युद्ध सहित कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार, करुणा और ज्ञान का अभ्यास सभी के लिए उपयोगी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो राष्ट्रीय मामलों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में विश्व शांति की संरचना बनाने की शक्ति और अवसर निहित है।

हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, जिससे कई कठिनाइयां आती हैं। जब शांत और स्पष्ट मन से सामना किया जाता है तो समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। इसके बजाय, जब हम घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण खो देते हैं, तो हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। हमारे दिमाग अंधे हो जाते हैं और उन उग्र क्षणों में युद्ध सहित कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार, करुणा और ज्ञान का अभ्यास सभी के लिए उपयोगी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो राष्ट्रीय मामलों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हाथों में विश्व शांति की संरचना बनाने की शक्ति और अवसर निहित है।

वर्तमान परिस्थितियों में, निश्चित रूप से मानवीय समझ और सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना की बढ़ती आवश्यकता है। ऐसे विचारों को प्राप्त करने के लिए, हमें एक अच्छा और दयालु हृदय उत्पन्न करना होगा, क्योंकि इसके बिना, हम न तो सार्वभौमिक खुशी प्राप्त कर सकते हैं और न ही स्थायी विश्व शांति। हम कागज पर शांति नहीं बना सकते। सार्वभौमिक जिम्मेदारी और सार्वभौमिक भाईचारे और बहनचारे की वकालत करते हुए, तथ्य यह है कि मानवता राष्ट्रीय समाजों के रूप में अलग-अलग संस्थाओं में संगठित है। इस प्रकार, एक यथार्थवादी अर्थ मेंए मुझे लगता है कि ये समाज ही हैं जो विश्व शांति के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करना चाहिए। समाजों को अधिक न्यायपूर्ण और समान बनाने के लिए अतीत में प्रयास किए गए हैं। असामाजिक ताकतों से निपटने के लिए महान चार्टर के साथ संस्थाएँ स्थापित की गई हैं। दुर्भाग्य से, ऐसे विचारों को स्वार्थ ने धोखा दिया है। पहले से कहीं अधिक, हम आज देखते हैं कि कैसे नैतिकता और महान सिद्धांत स्वार्थ की छाया से अस्पष्ट हो जाते हैं, खासकर राजनीतिक क्षेत्र में। एक विचारधारा है जो हमें राजनीति से पूरी तरह दूर रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि राजनीति अनैतिकता का पर्याय बन गई है। नैतिकता से रहित राजनीति मानव कल्याण को आगे नहीं बढ़ाती है, और नैतिकता के बिना जीवन मनुष्यों को जानवरों के स्तर तक गिरा देता है। हालाँकि, राजनीति स्वयंसिद्ध रूप से गंदी नहीं है। बल्कि, हमारी राजनीतिक संस्कृति के साधनों ने मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए उच्च आदर्शों और महान अवधारणाओं को विकृत कर दिया है। विश्व शांति के साथ व्यक्तिगत शांति की आज आवश्यकता है और इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों में गंभीरता की भी आवश्यकता है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

त्रैमासिक परीक्षा में कक्षा दसवीं व नवमी के विद्यार्थियों को बांट दिए एक जैसे प्रश्नपत्र

दामजीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला, गलती सामने आते बदले गए प्रश्न

बैतूल। दामजीपुरा वैसे भी सुर्खियों में रहता है, अब एक ताजा मामला ऐसा है जिसमें भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। बुधवार 18 सितंबर को कक्षा नवमी एवं दसवीं कक्षा के परीक्षाओं में एक जैसे प्रश्नपत्र देने का मामला सामने आया। हालांकि जैसे ही गलती का एहसास हुआ, बच्चों से प्रश्नपत्र वापस लेकर अलग प्रश्न देकर परीक्षा ली गई। जिम्मेदार तो इस बड़ी त्रुटि को मानवीय भूल बता रहे है, पर यहां सवाल यह है कि यही स्थिति यदि बोर्ड कक्षा के वार्षिक एग्जाम में होती, तो बच्चे का कितना वक्त जाया होता और मानसिक रूप से बच्चे परेशान होते वह अलग से। दामजीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के अलावा आठनेर क्षेत्र में भी इसी तरह की चूक होने की जानकारी प्राप्त हो रही है।

यह है पूरा मामला

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दामजीपुरा में कक्षा नवमी एवं दसवीं कक्षा के त्रैमासिक एग्जाम चल रहे हैं। बुधवार को जब बच्चे प्रश्न पत्र देने पहुंचे तो वे प्रश्न पत्र देखकर ही भौचक रह गए। दरअसल कक्षा नवमी और दसवीं दोनों ही कक्षाओं के बच्चों को वितरित किए गए प्रश्न पत्र कक्षाएं तो अलग.अलग थी लेकिन प्रश्नपत्र एक से थे, काफी बच्चे असमंजस में थे। क्योंकि कोर्स के बाहर के प्रश्न आने की वजह से वह प्रश्नपत्र हल ही नहीं कर पा रहे थे। इस संबंध में जब परीक्षक सहित अन्य स्टाफ को भनक लगी, तो तत्काल ही सभी बच्चों से प्रश्न पत्र वापस लिए गए, हालांकि कुछ बच्चे प्रश्न पत्र अपने साथ लेकर घर भी लौटे, जिन्होंने घर पहुंच कर बताया कि प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए हैं। शुक्र तो है यह त्रैमासिक परीक्षा थी और समय रहते प्रबंधन ने अपनी गलती को सुधार भी लिया। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब इस तरह की धांधली हो रही है और जिम्मेदार महकमा यदि यह कहे कि यह छोटी सी चूक थी कोई वार्षिक परीक्षा तो नही थी। जो चूक हुई, उसे सुधार लिया गया है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैतूल जिले का शिक्षा तंत्र किस ढर्रे पर चल रहा है।

अभिभावकों के पास पहुंचे प्रश्न पत्र

एक और जानकारी दी जा रही है कि बच्चों को प्रश्नपत्र अलग से दिए गए, वहीं दूसरी ओर दोनो कक्षाओं के बच्चे प्रश्नपत्र लेकर घर भी पहुंच गए। इससे यह भी संशय है कि दामजीपूरा से प्राचार्य सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी दी। अभिभावकों के मुताबिक कम समय के कारण बच्चे प्रश्न पत्र हल ही नहीं कर पाए।

इनका कहना

यह जानकारी अभी - अभी मेरे संज्ञान में आई। बच्चो को तत्काल दूसरे प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे।

- नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर बैतूल

सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में बैतूल को मिला ए ग्रेड

बैतूल। सीएम हेल्पलाइन की मासिक ग्रेडिंग माह अगस्त 2024 में बैतूल जिले ने प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। विगत 8 माह से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के कुशल मार्गदर्शन और सतत मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की कड़ी मेहतन का परिणाम रहा है कि बैतूल जिला सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में द्वितीय स्थान पर रहा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जिले की शिकायतों का 82.55 प्रतिशत संतुष्टि पूर्वक निराकरण कर बैतूल जिले ने ए ग्रेडिंग प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि जिले का संतुष्टि प्रतिशत भी प्रदेश के अन्य जिलों से उत्कृष्ट रहा है। सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग में सम्मिलित विभागों में से 44 विभागों द्वारा सकारात्मक निराकरण किया जाकर ए ग्रेडिंग प्राप्त की है। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं प्रदेश में जिला अव्वल आने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी है।

वन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण

संभाग आयुक्त श्री तिवारी ने बैठक में दिए निर्देश

बैतूल। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को आयोजित बैठक में संभागायुक्त नर्मदापुरम संभाग के.जी. तिवारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने विभाग के विकास कार्यों के लिए वनक्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए प्रकरण तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वन विभाग को भेजें। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर समय सीमा में भूमि आवंटन के

प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत विकास कार्य शुरू हो सके। बैठक में मुख्य वन संरक्षक नर्मदापुरम, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह, पंचायत के सीईओ अक्षत जैन के अलावा वन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में वनक्षेत्र में जल निगम की पेयजल योजनाओं, जल संसाधन विभाग की सिंचाई योजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी संभागायुक्त ने की। वन विभाग की सीमा से 250 मीटर के क्षेत्र में खनिज उत्खनन की स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए गठित समिति की बैठक भी संभागायुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि इस समिति की बैठक हर माह आयोजित की जाए। कमिश्नर ने बैठक में निर्देश दिए कि जंगलों से लगे बाहरी क्षेत्र में खनिज उत्खनन की अनुमति देने से पूर्व वन्यजीवों की सुरक्षा और वन क्षेत्र में लगे वृक्षों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित

बैतूल। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी, रेशम पालन, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों एवं कृषक समूहों से 10 अक्टूबर तक सर्वोत्तम कृषक समूह पुरस्कार, सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किये गए है। आवेदनकर्ता कृषक आवेदन फार्म कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर आत्मा कार्यालय से नि शुल्क प्राप्त कर सकते है। एक बार सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार (विकासखंड जिला राज्य समूह) प्राप्त प्रविष्टि आगामी 7 वर्षों तक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र आवेदक कृषक द्वारा पूर्ण भरा जाना एवं आवश्यक समस्त दस्तावेज मय फोटोग्राफ संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय बधिरता रोग एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण आयोजित

बैतूल। राष्ट्रीय बधिरता रोग एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को बहरेपन की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन के उद्देश्य से एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी में खंड चिकित्सा अधिकारी, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को प्रशिक्षित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रविकांत उइके ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य बधिरता वाले हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार दिया जाना है। उन्होंने बताया कि कान में पानी न जाने दे, कान में तरल पदार्थ न डाले, मवाद को साफ एवं गर्म कपड़े से साफ करें, मवाद में बदबू होना या खून आना गंभीर रोग के लक्षण हो सकते है, मवाद आते रहने से बहरापन हो सकता है। ऐसे लक्षण आने पर तुरंत स्वास्थ्य केन्द्र में जांच कराएं। उन्होंने बताया कि जन्म लेने वाले समस्त शिशुओं की बहरेपन की पहचान हेतु कान की जांच की जानी चाहिए, ताकि समय रहते उनका प्रबंधन कर बहरेपन से बचाया जा सके। सीएमएचओ श्री उइके ने बताया कि 23 सितंबर से 29 सितंबर तक जिले में अंतरराष्ट्रीय बधिरता सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह में स्कूलों एवं समुदाय में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत पदस्थ स्टाफ, जिले एवं विकासखंड स्तर पर पदस्थ स्टाफ तथा गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से जिले एवं विकासखंड स्तर पर विशेष श्रवण स्क्रीनिंग एवं पहचान शिविर आयोजित किए जाएंगे।

राहुल गांधी को आतंकवादी कहने पर भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

किसानों की समस्याओं और भाजपा नेताओं के बयान पर जताई आपत्ति

बैतूल। किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों की फसलों का उचित मूल्य दिलाने और भाजपा नेताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को

आतंकवादी कहने पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि वे किसानों के हित में सरकार को निर्देश दें और कांग्रेस नेताओं पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर सख्त कदम उठाएं।

राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस में रोष

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री वनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी कहा गया, जो बेहद अपमानजनक है। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की सेवा में अपना जीवन बलिदान किया। उनके परिवार की देशभक्ति किसी से छिपी नहीं है, और ऐसे में राहुल गांधी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आहत हैं।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें

ज्ञापन में किसानों के लिए निम्नलिखित मांगें रखी गई हैं-

1. सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया जाए और इसकी 100 प्रतिशत खरीदी की जाए।
2. गेंहू का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए।
3. किसानों की फसलों को भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए।
4. गढ़ा टोल प्लाजा को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे तत्काल बंद करने और हटाने की मांग की गई है।

ज्ञापन के अंत में कांग्रेस ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे भाजपा नेताओं वनीत सिंह बिट्टू और रघुराज सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश जारी करें और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाएं।

महिला के पेट में कपड़ा छोड़ने के मामले की जांच करने बैतूल पहुंची डिप्टी डॉयरेक्टर

बैतूल। जिला अस्पताल में महिला के सीजर ऑपरेशन होने के बाद पेट में ही कपड़ा छोड़ने की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद इस मामले की जांच करने डिप्टी डॉयरेक्टर सहित तीन सदस्यीय टीम बैतूल पहुंची। टीम ने सिविल सर्जन सहित सीजर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की। इसकी रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।

लापरवाही सामने आने पर संबंधित डॉक्टर पर गाज भी गिरने की संभावना हैं। जानकारी के मुताबिक जंबाडा निवासी गायत्री पति विजय रावत का जून माह में जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद से ही महिला के पेट में दर्द की शिकायत थीं। हाल ही में कुछ दिन पहले पेट दर्द होने पर महिला को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

डॉक्टरों ने महिला के पेट से ऑपरेशन कर कपड़ा निकाला। बताया गया कि सीजर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने कपड़े को ही छोड़ दिया। पेट में कपड़ा होने के कारण महिला को पेट दर्द की शिकायत थीं। इस पूरे मामले की शिकायत महिला के परिजनों द्वारा सीएमएचओ और सिविल सर्जन से की गई।

इस मामले की जांच करने के लिए सीएमएचओ ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया और जांच शुरु कर दी। पीड़ितों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग भोपाल ने गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवा संभाग भोपाल से टीम गठित की गई।

इस टीम में डिप्टी डॉयरेक्टर डॉ. नीरा चौधरी सहित दो अन्य डॉक्टर शामिल हैं। यह टीम भी गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले की जांच शुरु कर दी हैं। टीम द्वारा यह जानकारी जुटाई जा रही हैं कि इसमें डॉक्टर की लापरवाही तो नहीं है।

इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती हैं।

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छूटने के मामले की जांच के लिए जिला स्तरीय टीम गठित

बैतूल। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.रविकांत उइके ने बताया कि सीजर ऑपरेशन के दौरान जंबाड़ा निवासी श्रीमती गायत्री पति श्री विजय रावत के पेट में कपड़ा छोड़ दिए जाने का मामला 18 सितंबर को सामने आया था। इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय जिला स्तरीय टीम गठित की गई है, जो 7 दिवस में जांच कर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। क्षेत्रीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल से गठित टीम में डिप्टी डायरेक्टर डॉ. नीरा चौधरी एवं उनके दल द्वारा सूक्ष्मता एवं गहराई से जांच की जा रही है। भोपाल के दल द्वारा ऑपरेशन करने वाले चिकित्सा अधिकारी एवं स्टाफ से बयान लिये जा रहे हैं एवं संबंधित निजी चिकित्सालय, जहां कि पीड़ित महिला को भर्ती कराकर ऑपरेशन के पश्चात कपड़ा निकाला गया वहां के चिकित्सक एवं स्टाफ से भी बयान लिये जाकर जांच की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.उइके ने बताया कि चिकित्सीय कारणों से प्रकरण की संपूर्ण जांच में थोड़ा समय लगेगा। महिला के जिला चिकित्सालय में भर्ती होने के उपरांत से वर्तमान में हुए ऑपरेशन के बीच की समयावधि के एक-एक तथ्यों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए बिना जांच के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन होगा। प्रकरण की बिन्दुबार जांचों के उपरांत ही वस्तुस्थिति से जनसामान्य को अवगत कराया जा सकेगा।

रिटायर्ड रेलकर्मी की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बैतूल। रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दूधावानी में एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की हत्या का मामला सामने आया है। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की है। सूचना मिलते ही रानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह दूधावानी में सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी मुन्नालाल पिता कन्हैयालाल बरडे उम्र 75 वर्ष का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर जाकर जायजा लिया। पता चला कि अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर की है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए घोड़ाडोंगरी

स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक मुन्नालाल रेलवे में क्लर्क के पद पर पदस्थ थे। कुछ साल पहले वे सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद वे गांव में ही अकेले रहते थे। जिनका शव खेत में बने मकान के पास पड़ा मिला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरु कर दी हैं। उधर एक अन्य मामले में बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनारा में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी हैं।

गणेश विसर्जन के दौरान हिंसक झगड़े के मामले में पीड़ितों ने की एसपी से शिकायत

थाना गंज पुलिस ने मारपीट के आरोपी को किया गिरफ्तार

बैतूल। गणेश विसर्जन के दौरान राजेंद्र वार्ड में हुए हिंसक झगड़े के मामले में पीड़ितों ने शुक्रवार 20 सितंबर को एसपी से शिकायत कर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अंकुश मगरे और नवीन मगरे, निवासी राजेंद्र वार्ड ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि ग्रीन सिटी के मयूर और यश कावरे सहित 15-20 लोगों ने उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। अंकुश और नवीन मगरे ने बताया कि घटना के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने गंज थाने पहुंचे, तो उन्हें मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। लेकिन अनावेदक मयूर और उसके साथी ने ओपीडी में भी मारपीट की। पीड़ितों ने इसके बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने अगली रात 19 सितंबर को उनके घर पर आकर धमकी दी। आरोप है कि 19 सितंबर को दिनदहाड़े मयूर और उसके साथियों ने अंकुश और उनके भाई नवीन को उनके घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की, उनकी बहन को पाइप से मारा और उनकी माताजी को धक्का देकर गिरा दिया।

फुटेज के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग

अंकुश और नवीन ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज गंज मस्जिद के पास से 18 सितंबर की रात 9:30 बजे के और उनके घर के फुटेज 19 सितंबर दोपहर 3:22 के मौजूद हैं। पीड़ितों ने एसपी से इन फुटेज को संज्ञान में लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अनावेदक लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उनका पूरा परिवार डर और दहशत में जी रहा है।

बैतूल। 18/09/24 को फरियादी अकुंश पिता गणेश मगरे, उम्र 34 वर्ष, निवासी राजेन्द्र वार्ड, बैतूल ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गोलू उइके, यश कावरे और मयूर गोस्वामी ने गणेश विसर्जन के दौरान उसके साथ मारपीट की। इस रिपोर्ट के आधार पर थाना गंज में अपराध क्रमांक 330/24, धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 19/09/24 को उक्त आरोपीगण और उनके साथियों ने फिर से फरियादी के साथ धमकी, मारपीट की, जिसके आधार पर थाना गंज में अपराध क्रमांक 332/24, धारा 333, 296, 115(2), 191(2), 351(2) BNS 2023 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान आरोपी मयूर पिता कन्हैयालाल गोस्वामी, उम्र 22 वर्ष, निवासी लोहिया वार्ड को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक रविकांत डहेरिया, सउनि जीपी बिल्लोरे, प्र.आर. हितुलाल, प्रआर रामदास, आर नवीन, आर मनोज, आर अनिरुद्ध, और आर नरेन्द्र धुर्वे की विशेष भूमिका रही।

कांग्रेस ने प्रदेशभर में किसान न्याय यात्रा निकाली

इंदौर में पुलिस से झड़प, कांग्रेस कार्यकर्ता का सिर फूटा

उज्जैन में ट्रैक्टर से गिरे विधायक, होमगार्ड जवान की मौत ; भोपाल में बुलडोजर से रोकी रैली

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेशभर में किसान न्याय यात्रा निकाली।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े लीडर सड़कों पर नजर आए। ट्रैक्टर रैली निकाली गई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह प्रदर्शन का नेतृत्व किया। जीतू पटवारी ट्रैक्टर चला रहे थे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इस पर सवार रहे। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने मोर्चा संभाला। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ, तो आलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा को लीड किया।

पटवारी ने रुमाल से पोंछा कार्यकर्ता का खून

इंदौर में प्रदर्शन के दौरान चोइथराम चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। पुलिस से झड़प में एक कार्यकर्ता घायल हो गया। उसे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्रैक्टर के पास बुलाया और अपने रुमाल से खून पोंछा। कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल पहुंचाया गया है।

भोपाल में बुलडोजर से रोकी कांग्रेस की रैली

भोपाल में रातीबड़ से आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सूरज नगर तिराहे पर रोक लिया। खास बात ये है कि पुलिस ने कांग्रेस की रैली को रोकने के लिए यहां दो बुलडोजर खड़े कर दिए। कांग्रेस की इस यात्रा में करीब 150 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल रहे। बाद में कांग्रेस ने यहीं पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सोयाबीन का पौधा भी दिया।

उज्जैन में चलते ट्रैक्टर से गिरे कांग्रेस विधायक

उज्जैन में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पर बैठे कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस को चक्कर आ गया। जिससे वे चलते ट्रैक्टर से नीचे गिर गए। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें उठाया। विधायक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उज्जैन में न्याय यात्रा में होमगार्ड जवान की मौत

उज्जैन में किसान न्याय यात्रा के दौरान होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। वह बीमा अस्पताल चौराहे पर तैनात थे। इसी दौरान अचानक उसके सीने में दर्द हुआ। वहां मौजूद जवान उसे अस्पताल ले गए, जहां मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जवान को हार्ट अटैक आया था।

छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी

छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस दौरान पूर्व सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने भरी बारिश में यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और पीएम मोदी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन किसानों की आय तो आधी हो गई। नकुलनाथ ने ये भी कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया था।

देवास प्रेस क्लब चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी

देवास। देवास प्रेस क्लब के आगामी 28 सितंबर को सम्भावित चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। प्रेस क्लब सदस्यों के अलग अलग गुटों के अनेक सदस्यों ने अध्यक्ष पद को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश की है।

उल्लेखनीय है कि इस बार के चुनावों में कुछ अभिभाषक पत्रकार भी उम्मीदवार हैं वहीं एक अन्य गुट के कुछ सदस्यों ने कानून के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर इन चुनावों की पेचीदगियों के जिक्र से इन चुनावों को एक नया मोड़ दे दिया है। इसके साथ ही वर्तमान अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने इस बार कुछ नए सदस्य भी जोड़े थे जो नए वोट बैंक के रूप मे थे मगर कानूनन उन्हें भी न तो वोटिंग की और न ही चुनाव लड़ने की पात्रता है हालांकि सभी सदस्य यों तो बार बार ये कहते सुने जा रहे हैं कि इस बार सभी पदों के लिए सर्वानुमति बने मगर ये राह उम्मीदवारों की महत्वाकांक्षा के आड़े आ रही है।

देवास के अमृत संचय अभियान को मेपकॉस्ट से मिली सराहना/ मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने संरचनाओं को बताया सही दिशा में कदम

देवास। अमृत संचय अभियान के अंतर्गत देवास जिले मे जल संचय के लिए निर्मित संरचनाओं के निरीक्षण एवं अध्ययन के बाद मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने शुक्रवार को परिषद् के वैज्ञानिकों के अध्ययन की विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए। देवास में जल संचय के लिए बनी संरचाओं को सही दिशा में कदम बताया। उन्होंने जिला प्रशासन के नेतृत्व में जनभागीदारी से चलाए जा रहे अमृत संचय अभियान की सफलता की गाथा मध्यप्रदेश ही नहीं वरन देश के अन्य जिलों में भी दोहराई जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. कोठारी ने वैज्ञानिक निरीक्षण दल के प्रतिवेदन में अभियान को अनुकरणीय बताते हुए वर्षा जल संचयन की देवास जिले में निर्मित संरचनाओं के वैज्ञानिक पक्ष, स्थल चयन और लागत के साथ वैज्ञानिक अध्ययन को पुस्ताकाकार रूप देने की अनुसंशा भी की है। गौरतलब है कि 03 और 04 सितम्बर को म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के चार सदस्यीय टीम ने देवास की जल संरचनाओं का निरीक्षण कर वैज्ञानिक अध्ययन किया था।

उल्लेखनीय है कि देवास में बीते सौ दिनों में वर्षा जल के 225 करोड़ लीटर पानी को धरती में पहुँचाने के लिए जल संरचनाऐं निर्मित कर देश भर में एक बड़ी मिसाल कायम की है। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के नेतृत्व में अमृत संचय अभियान की छोटी सी टीम ने प्रसिद्ध जल वैज्ञानिक डॉ. सुनील चतुर्वेदी की अगुवाई में यह बड़ा काम कर दिखाया है।

टीम में जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु प्रजापति, एडीएम श्री प्रवीण फुलपगारे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रियंका मिमरोट, राज्य आनंद संस्थान की समन्वयक डॉ. समीरा नईम, पत्रकार श्री श्रीकांत उपाध्याय, वरिष्ठ नागरिक संस्था के श्री गंगासिंह सोलंकी, साहित्याकार श्री मनीष वैद्य, एक्ट-ईव फाउण्डेशन के श्री मोहन वर्मा, राज्य आनंद संस्थान के श्री महेश सोनी, सुश्री सफिया कुरैशी, सुश्री कृपाली राणा, श्री दीपक पोरवाल, तकनीकी सदस्य श्री हिमांशु कुमावत, श्री विशाल जगताप, विभावरी के श्री विपिन पंड्या, श्री कपिल जोशी, सुश्री सोनाली खड़से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती शर्मिला ठाकुर, सुश्री सुनीता कौशल, शिक्षक सुश्री मनीषा सोनी, पत्रकार श्री अरविंद त्रिवेदी तथा नगर निगम के श्री राजेश परमार ने ज़मीनी काम करते हुए तीन सौ से ज्यादा जल संरचनाऐं निर्मित करवाई। जिले में अभियान की गतिविधियाँ ज़ारी है तथा अब बोरी बंधान के काम को भी प्राथमिकता से किया जा रहा है।

दो माला मार्केट बनाने की जुगत में पुलिया ही गायब कर दी..

सभी जिम्मेदार सो रहे ऐसा क्यों..?

नर्मदापुरम- संजीव डे राय

एक दिन पहले ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर उसकी प्रति कलेक्टर को दी हैं । उसमें प्रशासनिक जिम्मेदारों को नगरीय अव्यवस्थाओं का आइना दिखाया। नगर में कितने तरह के अनियमित कार्य हो रहे वो अनैतिकता/ अवैध की श्रेणी में आते हैं। यह सच भी है कि, नगर में प्रशासनिक आला अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्यालय अव्यवस्थाओं का सिरमौर बन गया। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जबकि सरकार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने /करवाने में और शासकीय योजनाएं क्रियान्वित कराने हेतु करती है। लेकिन मुख्यालय पर अधिकांश जितने अधिकारी नियुक्ति हैं अपने दायित्वों से परे काम कर रहे हैं। प्रशासनिक आला अधिकारियों को (जिसमें पुलिस भी शामिल हैं) जो काम करना चाहिए करती नहीं है। जबतक कोई हादसा न हो जाए या सीधे शासन से कोई फरमान नहीं आ जाएं दायित्व निभाने की जूं इनके कानों में नहीं रैंगती ऐसा क्यों.? यातायात व्यवस्था के लिए मुख्यालय पर पुलिस पूरे दल-बल के साथ नियुक्त हैं लेकिन हर दिन जाम लगता है ऐसा क्यों..? नेता आते हैं तो यातायात पुलिस मुस्तैद रहती बाकी दिन खर्राटे भरती है क्यों..? कलेक्टर और एसपी को जुगलबंदी के साथ नगरीय व्यवस्था के लिए मौके बेमौके, स्वत साल छह महीने में पेट्रोलिंग करनी चाहिए जिससे अवांछित तत्व, अपराधियों, समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल असामाजिक तत्वों पर दहशत बनी रहें। इनका मैदानी दौरा करते रहने से पीड़ित उनसे क्षेत्र की तकलीफों को कह सकते हैं लेकिन ये अधिकारी अपने दफ्तरों से निकलना पसंद नहीं करते यहां तक जनसुनवाई में पहुंचने वाले पीड़ित को सहानुभूति का मल्हम तक लगा नहीं पाते.! अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व जनप्रतिनिधि हो रहे अनैतिक कार्यों की फेहरिस्त लिखकर पुलिस अधीक्षक को सिविल ड्रेस में बगैर गाड़ी के आने को कह रहें है क्यों.. तो एक दूसरा नेता जगह-जगह बिक रही शराब को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे है ऐसा क्यों.? यह तो शर्मनाक ही है कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तो नगर की पेट्रोलिंग नहीं करते इनके अधीनस्थ अधिकारी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं क्यों.. अखबारों में खबर आने के बावजूद ये अधिकारी खबरों पर ध्यान नहीं देते क्यों..? आखिर अव्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती क्यों..? जितना वेतन ये लेते हैं उस अनुपात में ये जिम्मेदार समाज को वापस क्या कर रहे..? फिर सिटी मजिस्ट्रेट बनाने का औचित्य क्या.. जब नेता और अधिकारी दोनों ही लापरवाह हैं। जिन्हें जगाने का काम भूतपूर्वो को करना पड़ रहा..! भवानी शंकर शर्मा जी ने तो नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर लिखा है और हम खुलासा कर रहे हैं। बाबई रोड़ स्थित बैंक कालोनी के सामने की पुलिया गायब कर दी है। यहां दो माला मार्केट निर्माण कर लिया गया। कल को अब बरसाती पानी की निकासी का परिणाम कौन भुगतेगा क्या जिम्मेदार बता पायेंगे..? नगरपालिका नगर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर क्या देख रही, नजूल और नगरीय प्रशासन अपना कितना दायित्व क्या निभा रहा, फिर वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी क्या वोट कबाड़ने तक सीमित है ऐसे कई सवाल आम आदमी के ज़ेहन में दौड़ना तो आम बात हो गई।

कमलनाथ के बंगले में जिला पंचायत अध्यक्ष को पीटा

छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप ; पीड़ित बोला-मुझे गालियां दीं

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के परासिया से कांग्रेस विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच मारपीट हो गई। घटना शुक्रवार को जिले के शिकारपुर स्थित पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर हुई। विधायक ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर दलाली करने का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि विधायक ने अपशब्द कहे थे। इसकी शिकायत कमलनाथ से भी की गई है।

कमलनाथ ने बुलाई थी कार्यकर्ताओं की बैठक

पूर्व सीएम कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद शुक्रवार को परासिया विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार भी मौजूद थे। सभी लोग पूर्व सीएम के ऑफिस में बैठे थे।

इसी दौरान, सोहन वाल्मीकि ने संजय पुन्हार पर भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस पर संजय पुन्हार भड़क गए। दोनों के बीच कहासुनी हो गई। नौबत मारपीट तक आ गई। आरोप है कि विधायक ने संजय पुन्हार की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और गार्ड ने बीच-बचाव किया।

विधायक सोहन वाल्मीकि बोले- मुझसे अभद्रता की

घटना के बाद परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि बैठक में शामिल नहीं हुए। वह बैठक शुरू होने से पहले वापस परासिया लौट गए। विधायक ने मीडिया को बताया, मारपीट हुई है।

संजय पुन्हार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं करते। वह दलाली करते हैं। वह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे। हमने कहा था कि ऐसे लोगों को चिह्नित करना चाहिए, जिससे संगठन को कमजोर होने से बचाया जा सके। यही बात इन्हें बुरी लगी। हमने कमलनाथजी को बोल दिया है कि ऐसे लोगों की संगठन में जरूरत नहीं है।

संजय पुन्हार ने कहा-
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विवाद

संजय पुन्हार का कहना है, यह पार्टीगत मामला है। कमलनाथ जी की बैठक से पहले विवाद हुआ। मैं भी बैठक के लिए गया था। बार-बार विधायक जी अपशब्द कह रहे थे। इसी को लेकर विवाद हो गया। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते विवाद हुआ है। पार्टी फोरम का मामला है। मारपीट नहीं हुई है। झूमाझटकी हुई है।

म.प्र. में विपणन संघ के गोदामों में खराब हो रहा अनाज, अब प्रदेश के बाहर भी बेचेगी सरकार

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के गोदामों में खराब हो रहे अनाज का विक्रय अब प्रदेश के बाहर गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जा सकेगा। मार्कफेड प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पर कृषि उपजों का क्रय कर उन्हें अपने गोदामों में रखता है।

लंबे समय तक अनाज गोदामों में रखे रहने पर वह खराब हो जाता है। मार्कफेड अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था, जिनके पास मप्र के अंदर मंडी समिति में लाइसेंस है इसके अलावा किसी अन्य को अनाज बेचा नहीं जा सकता है। ऐसे में राज्य के बाहर के व्यापारी यह कृषि उपज क्रय नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। राज्य के अंदर के लाइसेंसी व्यापारी इन कृषि उपजों का क्रय करने में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड ने वर्ष 2019 में जारी नियमों में संशोधन कर नए प्रावधान किए हैं।इसके अनुसार मार्कफेड राज्य के बाहर के गैर लाइसेंसी व्यापारी को भी अपनी कृषि उपज बेच सकेगा और स्वयं से माल उठाने का परिवहन अनुज्ञा-पत्र पोर्टल से जारी किया जाएगा।

हर साल लाखों का अनाज हो जाता है खराब- मार्कफेड के गोदामों रखा लाखों रुपये का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो जाता है। कई बार कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई हैं, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते न कर्मचारियों पर कार्रवाई हो पाती है और न ही अनाज को खराब होने से बचाया जा सकता है।

मध्याह्न भोजन की खुली पोल

पानी जैसी पतली सब्जी में आलू ढूंढते रहे मंत्री जी, गुस्से में अधिकारी को लगाया फोन

ग्वालियर (नप्र)। मध्यप्रदेश में मध्याह्न भोजन को लेकर कई तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें बच्चों को परोसा जा रहा मध्याह्न भोजन पानी की तरह नजर आता है। ऐसा ही कुछ मामला ग्वालियर जिले में सामने आया है, जिसमें मध्याह्न भोजन की मंत्री के सामने ही पोल खुल गई। ग्वालियर में आने वाली डीआरपी लाइन में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। यहां से निकले तो पास ही पीएमश्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल को देखा तो अंदर चले गए।

मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां स्कूल के बच्चे मध्याह्न भोजन के तहत भोजन कर रहे थे। जहां ऊर्जा मंत्री भी सहज रूप से खाना खाने बैठे गए। मंत्री जी को जब खाना परोसा गया तो वे दंग रह गए। सोयाबीन-आलू की सब्जी में आलू ही नहीं था और सब्जी इतनी पतली थी कि वे चौंक गए। मंत्री जी सब्जी में आलू ढूंढते नजर आए, लेकिन उन्हें आलू नहीं मिला। उन्हें पतली सब्जी पानी की से ही काम चलाना पड़ा।

इस तरह दाल में पानी देख मंत्री नाराज हो गए। तत्काल जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार को कॉल किया और नाराजगी जताई। मौके पर जांच के लिए मध्याह्न भोजन प्रभारी पहुंच गए। इस मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि गुरुवार के मेन्यू में सोयाबीन-आलू की सब्जी, दाल व रोटी दी गई थी। लेकिन क्वालिटी कैसी निकली यह क्षेत्रीय विधायक व मंत्री के सामने आ गया। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन की ऐसी तस्वीरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घोटाला देखने को मिलता है। यहां मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को सिर्फ पानी जैसी पतली सब्जी परोसी जाती है, जिसे कोई पशु भी नहीं खा पाएगा।

बेटा-बेटी के साथ नदी में कूदा युवक

पिता-पुत्र की मौत, बेटी की तलाश जारी ; रीवा में कर्ज से परेशान था

रीवा (नप्र)। रीवा में पिता अपने बेटा-बेटी के साथ टमस नदी में कूद गया। पिता का शव शुक्रवार सुबह 20 किलोमीटर दूर उत्तरप्रदेश में मिला। 4 साल के बेटे का शव पुल के पास मिला। एसडीईआरएफ की टीम 5 साल की बेटी की तलाश कर रही है।

घटना गुरुवार रात 9:30 बजे सोहागी थाना क्षेत्र के राजापुर पुल की है। पुल पर युवक की बाइक भी मिली है। मृतकों की पहचान सुनील मांझी (31) पिता राम निहोर मांझी निवासी पैरा टोला छिवलहिया, पुष्पराज मांझी (4) पिता सुनील मांझी के रूप में हुई है। बेटी पुष्पा (5) लापता है। शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से सर्चिंग शुरू की। सुबह करीब 9 बजे युवक का शव यूपी में मिला, जबकि करीब 10:30 बजे बच्चे का शव भी मिल गया। बताया जा रहा है कि सुनील कर्ज से परेशान था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया।

पिता बोले- रात में घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया-सुनील के पिता राम निहोर मांझी ने बताया, गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे बेटा दोनों बच्चों को लेकर बाइक पर निकला था। वह बच्चों को स्कूल ड्रेस दिलाने की बात कहकर गया था।

रात 9 बजे तक वह वापस नहीं आया तो बहू पूजा देवी ने फोन किया। इस पर सुनील ने थोड़ी देर में घर आने की बात कही। करीब आधे घंटे बाद फिर कॉल किया, तो फोन रिसीव नहीं किया। फिर रिश्तेदार संदीप मांझी को कॉल कर पूरी बात बताई।

संदीप ने भी सुनील के फोन पर कॉल किया, तो किसी अन्य व्यक्ति ने रिसीव किया। उसने बताया कि टमस नदी पर बने राजापुर पुल पर सुनील की बाइक खड़ी है। बाइक में चाबी लगी है। मोबाइल भी रखा है, लेकिन सुनील नहीं था। हम राजापुर पुल पहुंचे। आसपास तलाश किया, लेकिन बेटे और दोनों बच्चों का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

मौके पर सोहाग थाना प्रभारी पवन शुक्ला समेत पुलिस बल पहुंचा। अंधेरा होने के कारण नदी में तलाश नहीं की जा सकी। शुक्रवार सुबह एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने नदी में सर्चिंग शुरू की।थाना प्रभारी ने बताया कि पानी ज्यादा होने से नदी का बहाव तेज है। सुनील का शव बहकर उत्तरप्रदेश चला गया था। वहीं, पुल से थोड़ी दूर पुष्पराज का शव मिला। बच्ची की तलाश की जा रही है। फिलहाल कर्ज से परेशानी की बात सामने आ रही है।

6 महीने पहले लिया था लोन-राम निहोर ने बताया कि सुनील पेशे से किसान था। उसने परिवार और रिश्तेदारों का समूह बनाया था। इसमें सभी लोग पैसा इकट्?ठा करते थे। जरूरत पड़ने पर कोई भी लोन ले सकता था। 6 महीने पहले सुनील ने भी समूह से लोन लिया था। इसके अलावा, पिकअप भी खरीदी थी। उसके लोन की किस्त जा रही थी।

इंदौर से कटनी जा रही यात्री बस में अचानक लगी आग, देखते ही देखते हो गई खाक

दमोह(नप्र)। दमोह कटनी मार्ग पर कुम्हारी के आगे रेपुरा थाना क्षेत्र में इंदौर से कटनी जा रही यात्री बस में आग लग गई। इससे अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। सूचना मिलते ही रेपुरा और कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया।आग बहुत तेज थी और पूरी बस आग में जलकर खाक हो गई। गनीमत रही की बस में केवल दो यात्री सवार थे जिन्हें समय पर बाहर निकाल लिया, केवल ड्राइवर आग में झुलसा है। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवावाही रुक गई और जब आग शांत हुई तब यातायात चालू हुआ।जानकारी के अनुसार इस बस में सिर्फ दो ही यात्री सवार थे जिनको स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया।

प्रदेश अतिथि शिक्षकों की पूर्ति के लिये भी पारदर्शी तरीके से की जा रही कार्यवाही

शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में शासकीय स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। इनके आवेदन और ज्वाइनिंग से संबंधित सभी कार्यवाही ऑनलाइन प्रक्रिया से की जा रही है। ऐसी शासकीय शाला, जहाँ विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत थे और उस शाला में इस शैक्षणिक सत्र में भी रिक्त पद था। ऐसे संबंधित अतिथि शिक्षक स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इस शैक्षणिक सत्र में विभाग ने अतिथि शिक्षकों की सुविधा के लिये ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरु की है। इस व्यवस्था से मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को उपयुक्त शाला प्राप्त हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे आवेदक, जो पात्रता परीक्षा पास हैं. उन्हें 30 अंक तथा पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर 4 अंक प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 20 अंक प्रदान किये गये है। विभाग ने इस पद्धति से उनका स्कोर-कार्ड तैयार किया है। स्कोर कार्ड के मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को शाला आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

51 हजार 558 अतिथि शिक्षक दे चुके हैं उपस्थिति

प्रदेश में अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था को पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विगत वर्षों में विद्यालय स्तर पर तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किये गये हैं।

उक्त पैनल से पिछले शैक्षणिक सत्र में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आमंत्रण सुविधा अतिथि शिक्षक के ही लॉग-इन पर उपलब्ध करायी गयी है। इसका वेरिफिकेशन शाला प्रभारी द्वारा करने के बाद संबंधित अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग संबंधित शाला में ऑनलाइन की गयी है। अब तक इस व्यवस्था के तहत 51 हजार 558 अतिथि शिक्षक विभिन्न शासकीय शालाओं में उपस्थिति दे चुके हैं। इस व्यवस्था के बाद शासकीय विद्यालयों में नवीन रिक्तियों के लिये अतिथि शिक्षकों को आवेदन सुविधा प्रदान की गयी है, जिसमें आवेदक द्वारा ही रिक्त पदों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है।

नवीन रिक्तियों वाले 31 हजार 268 शासकीय स्कूलों में 2 लाख से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन दिये जा चुके हैं। इन आवेदकों द्वारा विकल्प का चयन किया जा चुका है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शीघ्र ही आवेदकों को ऑनलाइन पद्धति से ही स्कूलों का आवंटन किया जायेगा।

स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टर्स गैस राहत अस्पतालों में देंगे सेवाएं

भोपाल (नप्र)। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 15 डॉक्टर्स भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन गैस राहत अस्पतालों में सेवाएं देंगे। यह डॉक्टर्स 2 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि के लिये गैस राहत अस्पतालों में पदस्थ किये गये हैं।

भोपाल शहर में संचालित गैस राहत अस्पतालों में पदस्थ किये गये डॉक्टर्स में एक मेडिकल विशेषज्ञ, एक सर्जिकल विशेषज्ञ, एक अस्थिरोग विशेषज्ञ, एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ, एक निश्चेतना विशेषज्ञ तथा 10 चिकित्सा अधिकारी हैं। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये गये इन 15 डॉक्टर्स में से मेडिकल विशेषज्ञ ने जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में, सर्जिकल विशेषज्ञ एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ ने जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार कमला नेहरू चिकित्सालय में दो चिकित्सा अधिकारियों तथा जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, शाकिर अली खान चिकित्सालय व रसूल अहमद सिद्धिकी पल्मोनरी मेडिसिन सेंटर में एक-एक चिकित्सा अधिकारी ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा अधिकारियों की पदपूर्ति करने के लिये भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों की सेवाएं लेने का मांग पत्र भेजा था। स्वास्थ्य द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की मांग मानकर 27 अगस्त को 15 डॉक्टर्स की गैस राहत अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देने के आदेश जारी कर दिये।

होम लोन पर 1.80 लाख की सब्सिडी

कामकाजी महिलाओं को किराए पर मकान देगी सरकार ; पीएम आवास योजना की गाइड लाइन जारी

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च की गई थी। इस योजना का लाभ शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश में अगले 5 साल में 10 लाख नए मकान बनाए जाने की तैयारी है।

अलग-अलग कैटेगरी में नई पीएम योजना का फायदा इन चार तरीकों से लिया जा सकता है...

1. मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
2. सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी।
3. किराए पर भी मकान मिलेगा।
4. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने योजना की पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे राज्यों को भेजा गया है। राज्य सरकार केंद्र के साथ एमओए साइन करेगी। राज्य सरकारों को नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, उसी के बाद ये योजना लागू होगी।

शहर को मिलेगी एक और फ्लाई ओवर की सौगात

मंत्री श्री सारंग ने किया प्रभात चौराहे पर फ्लाई ओवर निर्माण स्थल का निरीक्षण

प्रभात चौराहे पर थ्री टियर ट्रैफिक सिस्टम, नीचे दो सड़कों पर वाहन, ऊपर चलेगी मेट्रो ; मंत्री सारंग बोले-9 महीने में कंप्लीट करेंगे

भोपाल (नप्र)। सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रभात चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रभात चौराहे पर नीचे ट्रैफिक, ऊपर फ्लाई ओवर और उसके ऊपर मेट्रो भी चलेगी। इससे रहवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।

रेलवे स्टेशन जाना होगा सुगम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि यह क्षेत्र के रहवासी सहित भोपाल और बीएचईएल के लोगों के लिये सौगात है। इस सुविधा से ट्रैफिक और रेल्वे स्टेशन की ओर जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। मंत्री श्री सारंग ने प्रस्तावित स्थल का जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित पीडबल्यूडी ब्रिज, मेट्रो, नगर निगम, विद्युत वितरण कंपनी, पुलिस और राजस्व के अधिकारियों के साथ संयुक्त दौरा किया।

समिति करेगी विभागीय समन्वय

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये समिति

बनाई गई है। यह समिति सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को गति देगी। समिति कार्य में आ रही बाधाओं एवं कठिनाईयों को सामने लाकर दूर करने का प्रयास करेगी। समिति संबंधित विभागों के साथ समय-समय पर बैठक करेगी और एक टाइम लाईन बनायेगी। लगभग 8 से 9 माह में फ्लाई ओवर तैयार करने की योजना है।

ग्रेड सेपरेशन और मेट्रो की कार्य योजना

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि भोपाल के लिये यह सौगात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भूमि-पूजन कर देंगे। उन्होंने बताया कि आईटीआई तिराहे से बोगदा पुल तक आरओबी के विकास की योजना में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करेंगे। ग्रेड सेपरेशन और मेट्रो की कार्य योजना को जल्द ही फाइनल किया जायेगा।

लेफ्ट टर्न क्लियरेंस पर ध्यान

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उपरोक्त कार्य में प्राथमिकता के आधार पर लेफ्ट टर्न क्लियर विकास पर ध्यान दिया जायेगा। मेट्रो तथा पीडबल्यूडी आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। मंत्री श्री सारंग ने केपिटल पट्रोल पंप के पास स्थित नाले पर पुलिया के चौड़ीकरण तथा सर्विस रोड़ का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश लोक निर्माण अधिकारियों को दिये। इस मौके पर महापौर श्रीमती मालती राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सीएम यादव बोले

कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ा रही कांग्रेस

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कहा-खरगे माफी मांगे ; पटवारी ने पाक को दिया जवाब

भोपाल (नप्र)। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू-कश्मीर पर दिए बयान पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा-आज तो गजब हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत में धारा-370 जम्मू-कश्मीर में हटाने के मसले पर, 35ए के हटाने के मसले पर खुलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की।

कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय है इस मसले पर तो क्या यह गठबंधन पाकिस्तान ने कराया है। इस बात के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात स्पष्ट करें। ये घोर निंदनीय बात होगी कि पाकिस्तान के झंडे को अगर कांग्रेस लागू कर रही है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।

कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगें और कांग्रेस को जवाब दें

मुख्यमंत्री ने कहा- जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं लेकिन आज भी यह यह दंश अगर सामने आ रहा है जो पाकिस्तान से हमने आजादी के बाद से इस मुद्दे को लेकर के जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूर्ववर्ती संगठन ने इस बात को रखा था कि धारा 370 यह

कलंक है और वह जब पूरे देश के सामने हट करके आज वह सामान्य राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है तो केवल चुनावी राजनीति के कारण से देश विरोधियों से हाथ मिलाना, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना, यह शर्म की बात है।

सीएम ने कहा- कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को कठोर शब्दों में जवाब देना चाहिए कि वह देश के उनके हालत वही निपट ले। लेकिन अब ये कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस के इस स्टेप के मामले में और कांग्रेस के नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन के मामले में ये प्रुफ हो गया है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।

जीतू पटवारी बोले- पाकिस्तान की क्या हैसियत वो भारत के मामले में पड़े

इधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- पाकिस्तान की हैसियत नहीं हैं कि वो भारत के मामले में कोई टिप्पणी करे। कांग्रेस पार्टी देश के संविधान के साथ उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कश्मीर की आवाम ने इतना भारी बहुमत दिया। इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के संविधान और राजनीतिक लोगों से प्यार है। सारे राजनीतिक दल वो किसी पार्टी का हो वो भारत का राजनीतिक दल कश्मीर को लेकर चिंतित होता है। पक्ष-विपक्ष रखता है। पाकिस्तान की क्या हैसियत वो भारत के मामलों में पड़े..।

शिवराज बोले-सिद्ध हुआ पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर-ताल एक हैं

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षामंत्री के बयान से ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान, कांग्रेस और जेकेएनसी के सुर-ताल एक ही है। वो बोले कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इनके इरादे और एजेंडा भी एक ही है, इसलिए राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बयान देते रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं।

जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सरकार की बड़ी योजना

सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जायेगी

भोपाल (नप्र)। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिये राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों को बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित कराने के लिये फ्री कोचिंग दी जायेगी। इसके लिये सरकार प्रदेश के सभी जनजातीय विकासखंडों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। इस प्रशिक्षण अकादमी के जरिये जनजातीय विद्यार्थियों को जेईई, नीट, क्लेट और यूपीएससी जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की बड़ी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग देकर इन्हें परीक्षाओं में सफल होने के गुर सिखाए जायेंगे। वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिये भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग दी जा रही है। अब सभी ट्राईबल ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का लाभ देने के लिये योजना की संशोधित डीपीआर तैयार कर ली गई है। शासन से स्वीकृति मिलते ही रानी दुर्गावती प्रशिक्षण अकादमी प्रारंभ कर दी जायेंगी।

मैपसेट के जरिये भी दिये जा रहे है कौशल प्रशिक्षण

जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्था मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मैपसेट) के माध्यम से वर्तमान में पीव्हीटीजी समूह एवं एसटी, एस.सी. विद्यार्थियों के लिये कई प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी संचालित किये जा रहे हैं। मैपसेट द्वारा पीव्हीटीजी समूह के 122 विद्यार्थियों के लिये आईसेक्ट के जरिये (मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, शिवपुरी एवं तामिया जिला छिंदवाड़ा में) एसटी वर्ग के 87 विद्यार्थियों के लिये (इंडस्ट्री बेस्ड, सेन्टर बेस्ड एवं सिपेट भोपाल में) तथा एससी वर्ग के 27 विद्यार्थियों के लिये (सिपेट भोपाल एवं ग्वालियर में), कुल 236 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैपसेट द्वारा गत वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 16 हजार 409 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 8 हजार 287 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कंपनियों/फर्मों में प्लेसमेंट मिल गया है। जारी वित्त वर्ष सहित आगामी वर्षों में में कुल 29 हजार 40 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिये मेपसेट तेजी से कार्य कर रहा है। इसको विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं का एम्पैनलमेंट किया जा रहा है। इच्छुक संस्थाओं के साथ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) के प्रकाशन की कार्यवाही भी की जा रही है।

जनजातीय वर्ग के हित में जारी हैं सरकार के महती प्रयास

पोषण आहार अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश की तीन विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह (पीव्हीटीजी) बैगा, भारिया और सहरिया परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1500 रूपये दिये जा रहे हैं। पोषणाहार के लिये अगस्त 2024 तक की राशि दी जा चुकी है। जनजातीय समुदाय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए सभी जनजातीय विकासखंडों में कला भवन स्थापित किये जायेंगे। इसके लिये अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास एवं विद्युतीकरण योजना नियम 2018 में संशोधन लाने के प्रस्ताव पर विभाग की कार्यवाही चल रही है।

प्रदेश में 5 नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं 2 नवीन 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय होंगे स्थापित

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत प्रदेश में 5 नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं 2 नवीन 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों की स्थापना स्वीकृति मिली है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में स्वस्थ, समृद्ध और विकसित मध्यप्रदेश आकार ले रहा है। हमारा लक्ष्य जनाकांक्षाओं की पूर्ति और प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं आयुष चिकित्सालय बनने से आयुष चिकित्सा अध्ययन एवं आयुष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को सुलभता होगी और नागरिकों को भी गुणवत्तापूर्ण आयुष चिकित्सा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

आयुर्वेद महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों की स्थापना से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार : आयुष मंत्री श्री परमार

आयुष मंत्री श्री परमार ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत प्रत्येक महाविद्यालय की स्थापना के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तरह प्रदेश को कुल 350 करोड़ रुपए की राशि नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सागर, शहडोल, बालाघाट, नर्मदापुरम एवं मुरैना जिले में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना होगी, इससे प्रदेश के समस्त संभागों में अब शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हो जाएंगे। श्री परमार ने बताया कि औषधीय वनस्पतियों से भरपूर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र बालाघाट में शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना होने से छात्र-छात्राओं को सुगम रूप से अध्ययन, शोध एवं गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

उद्योगपतियों व निवेशकों से संवाद, उनकी समस्याओं के समाधान और प्रदेश में औद्योगिकरण के विस्तार में सहायक हैं इन्वेस्टर समिट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

बैंगलौर, मुम्बई, कोयम्बटूर के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर हुई समिट के आए हैं सकारात्मक परिणाम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश, सभी क्षेत्रों में विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन निरंतर जारी है। हमारा प्रयास है कि देश-विदेश के निवेशक और उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करें और औद्योगिक गतिविधियों का संचालन करें। इससे प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। देश के विभिन्न भागों में हो रही इन्वेस्टर समिट से उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद, उनकी समस्याओं के समाधान और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उनसे साझा करने का अवसर मिलता है। यह परस्पर संवाद, आपसी विश्वास-सुरक्षा और भविष्य की संभावनाओं का आधार बनता है। अब तक हुई इन्वेस्टर समिट का प्रदेश को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है। इसी क्रम में बेंगलुरु और मुंबई के बाद अब कोलकाता में रोड शो अन्तर्गत इन्टरेक्टिव सेशन में निवेशकों से रू-ब-रू चर्चा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में असीमित निवेश के अवसरों पर कोलकाता में आयोजित सत्र में सहभागिता के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री निवास में मीडिया को दिए संदेश में यह बात कही।

27 सितम्बर को सागर में होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क के माध्यम से युवाओं, महिलाओं सहित सभी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से अभियान के रूप में गतिविधियां संचालित कर रही है। क्षेत्रीय स्तर पर जारी इन्वेस्टर समिट के आगामी क्रम में 27 सितंबर को सागर में समिट का आयोजन होगा। प्रदेश में कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग घर-घर में होता था, सागर क्षेत्र की तो यह विशेष पहचान था। वर्तमान में सागर क्षेत्र में खनिज सेक्टर भी प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। इससे पहले जबलपुर और ग्वालियर में समिट आयोजित हो चुके हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समिट के माध्यम से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को क्षेत्रीय स्तर तक ले जाने में मदद मिली है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के भूमि-पूजन और लोकार्पण का क्रम जारी है। साथ ही इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हम उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और उद्योगपति प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह के साथ इच्छुक हैं।

औद्योगिक गतिविधियों के विस्तारीकरण और विविधिकरण के लिए प्रदेश में पर्याप्त अवसर उपलब्ध- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में जो उद्योगपति पहले से सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों के विस्तारीकरण और विविधिकरण के लिए भी प्रदेश में अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार सहयोगात्मक रूख के साथ सकारात्मक वातावरण निर्मित करते हुए शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, खनन, वनीकरण एवं पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।